सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 57, नई दिल्ली । बुधवार, 07 मई 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया, वो हर कार्य में जीत सकता है।

03 दिल्ली में 55 जगहों पर बजेगा युद्ध सायरन, एयरपोर्ट कॉलोनियों समेत कहां-कहां होगी मॉक ड्रिल?
06 दुनिया भर में आ सकती है चीनी माल की बाढ़
08 ₹सोशल मीडिया पर देशविरोध का कारोबार: अभिव्यक्ति की आज़ादी ...

“परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र” अपने द्वितीय वार्षिकी समारोह में आपको आमंत्रित करता है

“परिवहन विशेष” हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से निष्पक्ष समाचार प्रदान करते हुए अपने 2 साल पूरे करने में सक्षम रहा। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टर्स का दिल से धन्यवाद।

---- सम्मान समारोह -----

दिनांक 17 मई 2025,
स्थान :- कंस्टीट्यूशन क्लब आफ इंडिया, रफी मार्ग, नई दिल्ली,
समय :- प्रात 10 बजे से शाम 7 बजे तक,
मुख्य अतिथि ₹श्री शंभू सिंह₹, आई.ए.एस. सचिव शिपिंग भारत सरकार (सेवा निवृत) शिपिंग मंत्रालय

आमंत्रित विशेष अतिथि

1. श्री चंद्रमोहन आईएएस सेवा निवृत
2. श्री अमर पाल सिंह जॉइंट कमिश्नर, भारत सरकार
3. श्री आर के भटनागर, आईएएस सेवा निवृत
4. साइकिलिस्ट योगेंद्र सिंह, परामर्शदाता
5. श्री एम के गिरी, अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भारत
6. श्री अनिल छिक्कारा, उपायुक्त परिवहन सेवा निवृत, परामर्शदाता
7. श्री महाराज सिंह, मोटर वाहन नियम/अधिनियम परामर्शदाता
8. श्री अजय शाह, सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
9. पायलट अनिल शर्मा सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
10. श्री प्रशांत चोपड़ा सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
11. श्री राजीव शरद सड़क सुरक्षा परामर्शदाता
12. डॉ भरत सिंह, शिक्षाविद् (प्रिंस इंस्टीट्यूट आफ इन्नोवेटिव टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश)
13. श्री हेतराम
14. श्री अशोक
15. श्री राहुल गुप्ता
16. श्री ए ई कौशिक
17. श्री अशोक सक्सेना
18. श्री अशोक नारंग
19. श्री बरुड ठाकुर अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय भारत
20. श्री नरेन्द्र

के साथ भारत देश में जनहित एवम् कल्याणकारी कार्यों में योगदान प्रदान करने वाले कार्यकर्ताओं/ संस्थाओं / ट्रस्ट को सम्मान प्रदान किया जाएगा।

‘परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र” के द्वितीय वार्षिकी समारोह में मुख्य रूप से

1. सड़को को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने,
2. दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने,
3. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?”
4. “सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता हैं बचाव ?”
5. “दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य कैसे बनाया जा सकता है?”

पर परामर्शदाताओं के विचार आप को प्राप्त होगे। इसके साथ इस समारोह में

1. वक्ताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
4. परिवहन विशेषज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े श्रेष्ठ एंकर, वीडियोग्राफर, रिपोर्टर्स, लेखक, ज्योतिषाचार्य, कवि एवम् सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

- संजय कुमार बाटला
संपादक

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सार्वजनिक सूचना — हवाई हमले से सुरक्षा हेतु अभ्यास (ड्रिल) 7 मई, बुधवार, 2025

प्रिय मित्रों,

7 मई को संभावित हवाई हमले से सुरक्षा हेतु एक पूर्व नियोजित अभ्यास (ड्रिल) आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा मानसिक रूप से तैयार रहना है।

कृपया घबराएं नहीं और बच्चों को अवश्य जागरूक करें, हवाई हमले से बचाव हेतु निम्नलिखित चेकलिस्ट को अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें

1. अलर्ट और सतर्कता

* एयर रेड सायरन की आवाज़ पहचानें।
* मोबाइल, रेडियो अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी अलर्ट प्राप्त करें।
* अफवाहों पर विश्वास न करें; केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें।

2. सुरक्षित स्थान (शरणस्थल)

* निकटतम बंकर अथवा सार्वजनिक शरणस्थल की जानकारी रखें।
* अपने घर में एक मजबूत, बिना खिड़की वाला कमरा चिन्हित करें।
* शरणस्थल तक शीघ्र पहुँचने का मार्ग पूर्वनिर्धारित रखें।

3. आवश्यक सामग्री तैयार रखें

* कम से कम तीन दिन का पीने योग्य जल।
* सूखा भोजन जैसे बिस्कुट, ड्राय फ्रूट्स आदि।
* प्राथमिक चिकित्सा किट।
* टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियाँ।
* पोर्टेबल रेडियो।
* आवश्यक दस्तावेज़ (पहचान पत्र, चिकित्सा रिपोर्ट, बैंक विवरण आदि)।
* मोबाइल चार्जर और पावर बैंक।

4. अंधकार और सुरक्षा

* रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट सुनिश्चित करें – सभी लाइटें बंद रखें।
* खिड़कियों को मोटे पर्दों, काले कागज़ या ब्लाइंड से ढकें।
* शीशों से दूर रहें; आवश्यकता पड़ने पर ज़मीन पर लेट जाएँ।

***5. अभ्यास और पूर्वतैयारी* v**

* परिवार के साथ हवाई हमले से बचाव की ड्रिल का अभ्यास करें।
* बच्चों को सुरक्षित स्थान और प्रक्रिया से अवगत कराएँ।
* पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखें और सामूहिक सहयोग सुनिश्चित करें।

6. हमले के पश्चात सावधानियाँ

* केवल सरकारी निर्देश मिलने पर ही बाहर निकलें।
* घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दें।
* किसी भी संदिग्ध वस्तु या बम को न छुएँ; तुरंत पुलिस अथवा संबंधित विभाग को सूचित करें।

7. सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर आचरण एवं सावधानियाँ

* अफवाहें न फैलाएँ। किसी भी सूचना को साझा करने से पूर्व उसकी सत्यता की पुष्टि करें।
* भावनात्मक या उकसाने वाली पोस्ट से बचें। यह शांति और सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है।
* सरकारी या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी सूचनाओं को ही आगे बढ़ाएँ।
* अनधिकृत वीडियो या फोटो साझा करने से बचें। इससे आतंक और भ्रम फैल सकता है।
* ₹सोशल मीडिया पर संयम और समझदारी, हमारी नागरिक जिम्मेदारी है।”

हम सब की सजगता और तैयारी ही हमारी सुरक्षा की कुंजी है, धन्यवाद।

– संजय सम्राट

विश्व एथलेटिक्स दिवस आज

एकदम से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानना, खेल के लिए अपने प्यार को कायम रखना और चाहे जो भी हो, फिनिश लाइन तक जाकर ही दम लेना। ये कुछ काफी बेहतरीन क्वालिटी हैं जो एक एथलीट की पहचान हैं। खेल के प्रति उनका समर्पण और प्यार प्रेरणा देने वाला है। दुनिया भर के लोग एथलीटों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सम्मानित और एथलेटिक्स के लिए उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का जश्न मनाने की जरूरत महसूस करते हैं। इसे पूरा करने के लिए हर साल, विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है।

एथलीटों को सम्मानित करने और उनसे समर्पण और प्रेरणा के सबक लेने के लिए दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। हम खेलों और खिलाड़ियों से सीखते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए यह खास दिन मनाना चाहिए।

विश्व एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, को दुनिया भर में मनाया जाने वाला है। यह सालाना कार्यक्रम दुनिया भर के एथलेटिक्स समुदाय द्वारा खेल और इसकी भागीदारी, एकता, शांति और उत्तर निष्पक्ष खेल के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हम चाहें एथलीट, कोच, अधिकारी या सिर्फ प्रशंसक हों, यह सभी उम्र और क्षमताओं के लोगों को एथलेटिक्स में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का खास दिन हैं।

विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास हर साल 7 मई को मनाया जाने वाला विश्व एथलेटिक्स दिवस का बेहद प्रभावशाली इतिहास है। इस खास दिन को मनाए जाने की शुरुआत 1996 में अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन (आईएएएफ) के तत्कालीन अध्यक्ष प्राइमो नेबियोलो की दूरदृष्टि के कारण हुई थी। उन्होंने एथलेटिक्स के मूल्यों को बढ़ावा देने और नौजवानों के बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए समर्पित एक दिन की कल्पना की और वैश्विक पहल के रूप में ₹बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स₹ नाम से एक सामाजिक जिम्मेदारी परियोजना को लॉन्च किया था।

विश्व एथलेटिक्स दिवस का महत्व दुनिया भर में 200 से अधिक देशों में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, स्वास्थ्य केंद्रित चर्चाओं और जागरूकता अभियानों के जरिए एथलेटिक उपलब्धियों, प्रतिभा विकास और समुदायों पर खेल के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाती है। यह पहल सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देता है।

PCOS और हार्मोन्स पर गर्मी के मौसम पर हो सकता है बुरा असर, जानिए क्या कहते एक्सपर्ट

पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी की PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। जिससे काफी महिलाएं प्रभावित हैं और उनको इसके कारण रोजमर्रा की जिंदगी में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। PCOS होने पर महिलाओं के पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं, मूड स्विंग्स, वेट बढ़ना और एक्ने जैसी समस्या होती है। हालांकि उम्र और मौसम के हिसाब से भी कई बार इस कंडीशन में बदलाव आता है। गर्मी के मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से शरीर को एक हेल्दी बैलेंस मिलता है, जिससे PCOS के लक्षण कम होने लगते हैं। ऐसे में आप कुछ बातों का ध्यान रखकर इस कंडीशन को मैनेज कर सकती हैं।

फॉलो करें ये टिप्स

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो गर्मियों में नेचुरल रिदम की वजह से शरीर में काफी बदलाव आते हैं। इस मौसम में कुछ बातों का खास ख्याल रख कर आप हार्मोनल हेल्थ का ध्यान रख सकती हैं।

गर्मियों में हाइड्रेटेड रहना हार्मोनल हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। सही हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। साथ ही डाइजेशन में भी सुधार होता है।

गर्मियों में अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। वहीं PCOS को मैनेज करने के लिए भी पुदीना, नींबू या फिर चिया सीड्स का डिटॉक्स वॉटर पीना चाहिए। इनमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।

वहीं हल्दी-फुल्की एक्सरसाइज भी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ हार्मोनल हेल्थ को सुधारने और ब्लोटिंग की समस्या को कम करने में सहायता करती है।

प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर वाले ड्रिंक और अधिक कैफीन का सेवन करने से बचना चाहिए। क्योंकि इससे हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव होता है।

एंटी-इंफ्लेमेटरी और हार्मोनल फ्रेंडली डाइट गर्मियों में सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसलिए विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूज सीजनल फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

रेगुलर एक्सरसाइज भी PCOS को मैनेज करने में अहम भूमिका निभाती है। सुबह या शाम के समय आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ब्रिक्स वॉकिंग, स्वीमिंग और योग कोर्टिसोल लेवल कम करने के PCOS के लक्षणों को मैनेज करने में सहायता कर सकते हैं।

गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, जिसका अहम स्लीपिंग पैटर्न पर भी होता है। वहीं अच्छी और गहरी नींद हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी होती है। इसलिए इस मौसम में बेड टाइम रूटीन पर खास ध्यान देना चाहिए। सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल न करें और सोने से लिए सुकून भरा ठंडा वातावरण बनाएं।

बता दें कि अच्छी और गहरी नींद कोर्टिसोल, इंसुलिन और मेलाटोनिन हार्मोन को मैनेज कर सकती हैं। यह PCOS के लक्षणों को कम या अधिक करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

इसके साथ ही गर्मी के मौसम में 10-15 मिनट सूरज की रोशनी में रहना ओवरियन फंक्शन को सुधारता है। यह शरीर में विटामिन डी के लेवल को मैनेज करने के साथ इंफ्लेमेशन को कम करता है और मूड सुधारता है।

दूध के साथ सत्तू मिलाकर पीने से मिलेंगे ये 6 फायदे, गर्मी से भी मिलेगी राहत....

बिहार, उत्तर भारत, मध्यप्रदेश के रहने वालों के काम करने की जुझारू प्रवत्तियों का राज़...

उच्च प्रोटीन सामग्री-

सत्तू में प्रति 100 ग्राम में 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है, जो इसे शाकाहारियों और शाकाहारियों के लिए सबसे अच्छा और सबसे मूल्यवान स्रोत बनाता है।

आंत के स्वास्थ्य के लिए फाइबर -

इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है, कब्ज से राहत देता है और आपको लंबे समय तक तृप्त रखता है।

दूध के साथ सत्तू मिलाकर पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और पाचन क्षमता में सुधार होता है।

गर्मियों के दिन चल रहे हैं।

इन दिनों लोग अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट शामिल करना पसंद करते हैं।

इसके अलावा, हीट वेव और लू से बचने के लिए छाछ, दही, फ्रूट जूस और सत्तू जैसी चीजों का सेवन करते हैं।

ये तमाम चीजें न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, बल्कि बीमारियों से बचाव करने में भी मदद करती है।

खासकर, अगर सत्तू की बात करें, तो यह हमारे हेल्थ के लिए लाभकारी है।

कुछ लोग इसे सादे पानी में मिक्स करके पीना पसंद करते हैं।

जबकि कुछ लोग इसे दूध में घोलकर पीते हैं।

आपको बता दें कि दूध के साथ सत्तू पीने के बहुत लाभ होते हैं।

हमारे यहां पारंपरिक रूप से दूध के साथ सत्तू पीने का चलन है।

लेकिन, क्या आप इसके फायदों के बारे में जानते हैं?

नहीं, तो जानने के लिए लेख पूरा पढ़ें।

दूध के साथ सत्तू मिलाकर पीने के फायदे-

(1). प्रोटीन से भरपूर...

₹सत्तू पौधे-आधारित प्रोटीन का बेहतरीन अच्छा स्रोत है।

जब आप इसे दूध के साथ मिक्स करके पीते हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व बढ़ जाते हैं।

यह मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है।

इससे मसल्स रिपेयर होती हैं और बेहतर तरीके से विकास करती हैं।₹

(2). पोषक तत्वों का स्रोत..

₹जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बताया है कि सत्तू प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है।

इसके अलावा, सत्तू में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई तरह के पोषक तत्व होते हैं।

जब इसे दूध के साथ मिलाया मिक्स करके पिया जाता है, तो यह पोषण प्रोफाइल को बढ़ाता है।

इसमें विटामिन और मिनरल्स भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं।

(3). एनर्जी बूस्टर...

सत्तू और दूध को मिक्स करके पीने से एनर्जी बूस्ट होती है।

'गर्मियों के दिनों में लोग अक्सर थकान और कमजोरी महसूस करते हैं।

ऐसा बढ़ती गर्मी के कारण होता है।

गर्मी की वजह से शरीर में तेजी से पानी की कमी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन की शिकायत देखने को मिलती है।

इस तरह, शरीर कम काम करने के बावजूद जल्दी थकान और कमजोरी से भर जाता है।

वहीं, अगर आप नियमित रूप से सत्तू और दूध को नाश्ते में पीते हैं, तो पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे।

विशेषज्ञों की मानें, तो सत्तू इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है।

सत्तू में कार्बोहाइड्रेट, दूध में प्रोटीन और फैट होता है, जो एनर्जेटिक बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं"

(4). पाचन क्रिया में सुधार..

गर्मियों के दिनों में लोग कुछ भी अच्छा खाने से पहले कई बार सोचते हैं।

ऐसा इसलिए, क्योंकि इन दिनों हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है।

'इन दिनों अगर कोई तला-भुना या फ्राइड चीजें खाता है, तो इसका बुरा असर हमारी पाचन क्षमता पर देखने को मिलता है।

वहीं, अगर आप सत्तू का सेवन करते हैं, तो न सिर्फ पाचन क्षमता में सुधार होता है, बल्कि पेट से जुड़ी बीमारियों में भी कमी आती है।

सत्तू में डाइट्री फाइबर होता है, जो पाचन में सहायता करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है।

दूध में प्रोबायोटिक्स भी होते, हैं जो गट हेल्थ को बढ़ावा देते हैं।'

(5). वेट लॉस में मददगार...

'दूध के साथ सत्तू का सेवन करने से वेट लॉस में मदद मिलती है।

इसे आप वेट लॉस डाइट का एक हिस्सा बना सकते हैं। दरअसल, इसमें हाई फाइबर और प्रोटीन कंटेंट होता है, जो आपको लंबे समय तक पेट भरे होने का अहसास कराता है।

इस तरह आपका भूख में कंट्रोल रहता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं।'

(6). हड्डियों के लिए लाभकारी...

'दूध में कैल्शियम और सत्तू में मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है।

ये सभी तत्व हड्डियों को सपोर्ट करते हैं।

इससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

साथ ही हड्डी से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद भी मिलती है।'

तो फिर देर किस बात की, शुरू कीजिये अपनी दिनचर्या दूध और सत्तू के साथ और हरा दीजिये गर्मी को।

प्रश्न आया है कि क्या किसी भी राष्ट्र की कानून/व्यवस्था द्वारा उसकी संस्कृति/इतिहास से उसे काटा/पृथक किया जा सकता है? क्या बहुसंख्यक सनातन समाज की आस्था पर कुठाराघात करना उचित है?

सनातन संस्कृति में जैसे भगवान श्रीराम का स्थान है वैसे ही गाय भी करोड़ों बहुसंख्यक सनातनियों के लिए गहन आस्थागत भावना का विषय है। उसे केवल मजहबी चश्मे से देखना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि गाय सनातन परिवार/समाज की आर्थिक-सामाजिक-पर्यावरण समरसता के लिए साथी/सहायक रही है। गाय इस भारतीय भूखंड की चिरपुरातन सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रही है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। सनातन के साथ-साथ

उसकी सैन्य-शक्ति 'सिख पंथ' के लिए भी गौरक्षा महत्त्वपूर्ण रही है। इसी कारण दशकों से वृहद भारतीय समाज, संवैधानिक मर्यादा में रहकर गोहत्या/गोकशी पर प्रतिबंध की माँग करता आ रहा है। आज़ घर में कुत्ता पालना एक स्टेटस सिंबल बन गया है तब वह हमारे घर के एक सदस्य-समान हो जाता है, उसकी मृत्यु हमें रूला देती है। उसकी हत्या करके उसे भोजन की थाली में परोसना कभी किसी को नहीं भायेगा। इसी प्रकार जो गाय/गौशक्ति हमारे जीवन का आधार रही हो, हमारी प्रार्थना का अंग रही हो, उसकी हत्या सनातन/बहुसंख्यक समाज के मन/मानस पर कुठाराघात/अत्याचार ही माना जायेगा। लेकिन जिन्हें अक्सर स्वघोषित सेक्युलरिस्ट/वामपंथी/स्वयंभू उदारवादी/इब्राहीमी समाज का एक वर्ग उनको 'सांप्रदायिक' घोषित कर देता है। उनका तर्क होता है कि यह उनके पसंदीदा खाने के मौलिक अधिकार पर आघात है। किसी वर्ग के जीभ के अग्रभाग का थोड़ा-सा स्वाद इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना किसी बहुसंख्यक सनातन समाज की आस्था पर कुठाराघात है।

विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का यह फेमस मंदिर, जानिए कैसे पहुंचे

कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों में भगवान शिव से क्षमा मांगनी पड़ी थी। ऐसे में भगवान शिव ने लुका-छुपी का एक खेल खेला। जिसके तहत पांच अलग-अलग स्थानों पर पांच मंदिरों की स्थापना हुई। जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेशर शामिल हैं।

हमारे देश में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं। अगर आप भी प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो आज हम आपको तुंगनाथ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल, यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर की गिनती पंच केदार यात्रा में की जाती है, जोकि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित पांच पवित्र जगहों में से एक है, हालांकि यह चार धाम यात्रा से अलग है।

पौराणिक कथा के मुताबिक कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों में भगवान शिव से क्षमा मांगनी पड़ी थी। ऐसे में भगवान शिव ने लुका-छुपी का एक खेल खेला। जिसके तहत पांच अलग-अलग स्थानों पर पांच मंदिरों की स्थापना हुई। जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेशर शामिल हैं। इनमें से तुंगनाथ मंदिर तीसरा और सबसे अहम शिव मंदिर है।

सबसे ऊंचा शिव मंदिर

तुंगनाथ मंदिर न सिर्फ पंच केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा है, बल्कि यह विश्व का भी सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह मंदिर 3,680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल के पांडवों से जुड़ा है। यहां के स्थानीय लोगों की मानें, तो 8वीं शताब्दी के दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने मंदिर की खोज की थी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कत्यूरी शासकों ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था।

तुंगनाथ मंदिर

बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर के खुलने की तारीख तय की जाती है। उत्तराखंड में चार धामों की शुरुआत के साथ तीसरे केदार तुंगनाथ का उद्घाटन होता है। आमतौर पर अप्रैल या मई में वैशाख पंचमी पर यह मंदिर भक्तों के लिए खुल जाता है।

ट्रैक के जरिए पहुंचे

तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको उत्तराखंड के चोपता आना होगा। चोपता से तुंगनाथ तक का ट्रेक करीब 3.5 किमी का है। हालांकि यह ट्रैक ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको आसान भी नहीं कहा जा सकता है। इस ट्रैक के दौरान आपको घास के मैदान और बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चोपता से तुंगनाथ पहुंचने में करीब 2 से 3 घंटे तक का समय लगता है।

ऐसे पहुंचे चोपता

उत्तराखंड के चोपता से तुंगनाथ ट्रेक की शुरुआत होती है। ऐसे में आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा, फिर वहां से चोपता के लिए बस या टैक्सी करें। या फिर आप उखीमठ से बस ले सकते हैं। उखीमठ से आप लोकल टैक्सी ले सकते हैं। चोपता उत्तराखंड का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसको 'भारत का मिनी स्विटजरलैंड' भी कहा जाता है।

चंद्रशिला शिखर

बता दें कि तुंगनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा की राजसी चोटियों को भी देख सकते हैं। मंदिर तक जाने के बाद अगर आप चंद्रशिला शिखर तक जाना चाहते हैं, तो आपको तुंगनाथ मंदिर से आगे 1.5 किमी जाना होगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस शिखर पर भगवान श्रीराम ने ध्यान किया था।

हाथों की ढीली स्किन बनेगी कोमल और मुलायम, टाइट और शाइनी बनेगी त्वचा

अगर आप भी हाथों की स्किन को टाइट और सुंदर करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आप सप्ताह में आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। जिससे आपके हाथों की स्किन टाइट होगी और हाथ भी सुंदर दिखेंगे।

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल की वजह से खानपान और त्वचा से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। स्किन केयर के लिए महिलाएं कई महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हाथों की केयर करने के बारे में भूल जाती हैं। जिसकी वजह से हाथों की स्किन ढीली और बेजान नजर आने लगती हैं। इस वजह से महिलाएं उम्र से पहले बूढ़ी नजर आने लगती हैं। ऐसे में अगर आप भी हाथों की स्किन को टाइट और सुंदर करना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आप सप्ताह में आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। जिससे आपके हाथों की स्किन टाइट होगी और हाथ भी सुंदर दिखेंगे।

इस तेल से करें हाथों की मालिश

बता दें कि बादाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और बादाम का तेल स्किन के लिए लाभकारी होता है। बादाम के तेल में कई गुण और विटामिन पाए जाते हैं। बादाम का तेल स्किन की नमी बनाए रखने और त्वचा में कसाव लाने का काम करता है।

ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें।

अब थोड़ा सा बादाम का तेल अपने हाथों में लें।

फिर इस तेल से हाथों की अच्छे से मसाज करें।

इस उपाय को सप्ताह में दो दिन जरूर करें।

एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल

एलोवेरा जेल में कई सारे गुण पाए जाते हैं और यह सभी गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। एलोवेरा जेल में एंटी-ऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं। जोकि स्किन पर ग्लो लाने का काम करते हैं। साथ ही यह स्किन को टाइट और कोमल बनाने में सहायता करते हैं।

ऐसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले हाथों को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें अब इस जेल को हाथों पर अप्लाई करें और फिर 20 मिनट बाद अपने हाथों को ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय को सप्ताह में दो बार करना चाहिए।

कानपुर के रहने वाले एक अनजान ने दान किया बोन मैरो, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को मिला जीवनदान

राजस्थान के 12 वर्षीय थैलेसीमिया पीड़ित प्रथम को कानपुर के 35 वर्षीय रोहित ने बोन मैरो दान करके नई जिंदगी दी। ढाई वर्ष पहले हुए प्रत्यारोपण के बाद बच्चा स्वस्थ है और उसका ब्लड ग्रुप भी बदल गया है। भारत में बोन मैरो दान पंजीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। थैलेसीमिया से पीड़ित राजस्थान के रहने वाले एक 12 वर्षीय बच्चे प्रथम और उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले 35 वर्षीय रोहित का आपास में कोई रिश्ता नहीं है।

एक अनजान होते हुए भी रोहित ने अपना बोन मैरो दान कर प्रथम को नई जिंदगी दी। ढाई वर्ष पहले हुए बोन मैरो प्रत्यारोपण के बाद बच्चा अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसका ब्लड ग्रुप भी ए से बदलकर ओ हो गया है।

मरीज व डोनर दोनों का ब्लड ग्रुप एक हो गया। प्रथम बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है। मंगलवार को एक गैर सरकारी संगठन डीकेएमएस फाउंडेशन इंडिया की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में दोनों मिले, उनके चेहरे खिले थे।

प्रथम ने रोहित को अपना सुपरहीरो बताया

बच्चे ने रोहित को अपना सुपर हीरो बताया, लेकिन यह भी जागरूकता के अभाव में थैलेसीमिया से पीड़ित ज्यादातर बच्चों को ऐसा सुपर हीरो नहीं मिल पाता। डाक्टर बताते हैं कि थैलेसीमिया से पीड़ित एक से डेढ़ प्रतिशत मरीजों को ही बोन मैरो प्रत्यारोपण हो पाता है।यदि बोन मैरो दान के लिए जागरूकता बढ़े तो रक्त विकार की इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर बच्चों का स्थायी इलाज हो सकता है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं सांसदों ने उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली वासियों पर थोपे जा रहे कृत्रिम जल संकट के संबंध में ज्ञापन सौपा

मुख्य संवाददाता,/सुषमा रानी

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चांदोलिया, कमलजीत सहरावत, प्रवीन खंडेलवाल एवं बाँसुरी स्वराज आज दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना से मिले और उपराज्यपाल को आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली वासियों पर थोपे जा रहे कृत्रिम जल संकट के संबंध में ज्ञापन सौपा।

इस ज्ञापन में कहा गया है की दिल्ली के लोग आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हरियाणा राज्य की भाखड़ा नहर से जल आपूर्ति में कटौती की घोषणा कर दिल्ली पर एक कृत्रिम जल संकट थोपने का कार्य किया है।

महोदय, भाखड़ा डैम नहर में जल की कोई कमी नहीं है, फिर भी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु भाखड़ा नहर से जल आपूर्ति में भारी कटौती की घोषणा की है।

महोदय, दिल्ली को अपनी जल आपूर्ति का 50% से अधिक हिस्सा हरियाणा से प्राप्त होता है और हमें आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी कृषि प्रधान राज्य, जब वह जल संकट का सामना कर रहा हो, तो पहले अपने जल संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेगा।

वास्तविकता यह है कि दिल्लीवासियों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया है, और अब राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लगभग पूर्ण जल संकट की स्थिति की ओर धकेल दिया है।

हम इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और दिल्ली को अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्मित जल संकट से बचाने हेतु समाधान सुनिश्चित करें।

माउंट आबू ज्ञान सरोवर में मीडियाकर्मियों का पॉंच दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

माउंट आबू ब्रह्माकुमारी संगठन के ज्ञान सरोवर में चल रहे मीडियाकर्मियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के खुले सत्र को सम्बोधित करते केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान पूरी मेहनत के साथ देश के पालन-पोषण प्रयासरत रहता है। धरतीपुत्रों को वर्तमान समय में विभिन्न खेती व प्राकृतिक खेती की तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का देश को आर्थिक व सामाजिक रूप से विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शोषित, पीड़ित व वंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए मीडियाकर्मियों को हमेशा अपने नेत्रों को खुला रखना है।

संगठन के विज्ञान व तकनीकी प्रभाग के अध्यक्ष मोहन सिंघल ने कहा कि हर व्यक्ति की नज़र हमेशा मीडिया की तरफ ही रहती है। मीडिया संसार के हर कोने में हो रही घटनाओं को पलक झपकते ही एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देता है। इसी तरह से राजयोग भी मन को एक सैकेंड में इस लौकिक जगत से अलौकिक जगत ब्रह्माण्ड में रहने वाली परमशक्ति से जोड़ देता है।

संगठन के महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका डॉ. सविता अरोड़ा, *साहित्य संपादक, कवि एवं शिक्षाविद् डॉ. विवेक गौतम*, सोनीपत डीआईपीआरओ राकेश गौतम, ओम शांति मीडिया एडिटर डॉ. बी.के. गंगाधर, राजयोग प्रशिक्षिका बी.के. योगिनी बहन ने भी मीडिया के विभिन्न विषयों के तहत मीडिया को सशक्त बनाने, समाज को नई दिशा देने, वर्तमान चुनौतियों में मीडिया की सकारात्मक भूमिका तथा मीडिया कर्मियों को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला।

मल्टी मीडिया प्रमुख सह प्रभाग अध्यक्ष बी०के ०करुणा, प्रभाग उपाध्यक्ष बी० के० आत्मप्रकाश, दिल्ली से आये एक समाचार पत्र के एक्ज़ीक्युटिव चीफ़ एडिटर विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बी०के० शान्तनु, बी० के० निकुंज, बी० के० सुशांत, बी० के० सरला, जयपुर क्षेत्रीय संयोजिका बी० के० चंद्रकला, डॉ० बी० के० रीना आदि ने भी " वैश्विक शांति और सदभाव के अग्रदूत के रूप में मीडिया की भूमिका "विषय पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

वहीँ, कार्यक्रम में देश भर से शामिल हुए मीडियाकर्मियों को शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्ष बी० के० शीलू बहन ने राजयोग का अभ्यास कराते हुये गहन शांति की अनुभुति कराई।

समाज सेवा की खातिर नौकरी से वीआरएस लेने वाले ऋषिपाल ने नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों को दी बधाई

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। अंबेडकर नगर के भाजपा नेता ऋषिपाल समाज सेवा में एक जाना पहचाना नाम है। लगभग 30 वर्षों से वह समाज की विभिन्न रूपों में सेवा करते आ रहे हैं। भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भी वह पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। समाज सेवा के दौरान कई बार उनकी नौकरी आड़े आ जाती थी। यही कारण है कि उन्होंने समाज सेवा की खातिर अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। भाजपा नेता ऋषिपाल ने मदनगीर के मंडल अध्यक्ष दिलीप देवातवाल के दोबारा मंडल अध्यक्ष बनने एवं दक्षिणपुरी के मंडल अध्यक्ष के रूप में अमित चौटाला की नियुक्ति पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दोनों युवा मंडल अध्यक्ष जुझारू, कर्मठ एवं ईमानदार हैं। यह पार्टी को मजबूती देने की दिशा में दिन रात कार्य करते रहे हैं। पार्टी ने इन्हें मंडल अध्यक्ष बनाकर एक बहुत ही उचित निर्णय लिया है।ऋषिपाल ने कहा कि समाज सेवा से मुझे संतुष्टि मिलती है और मैं पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करता रहूंगा तथा लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना अधिक से अधिक

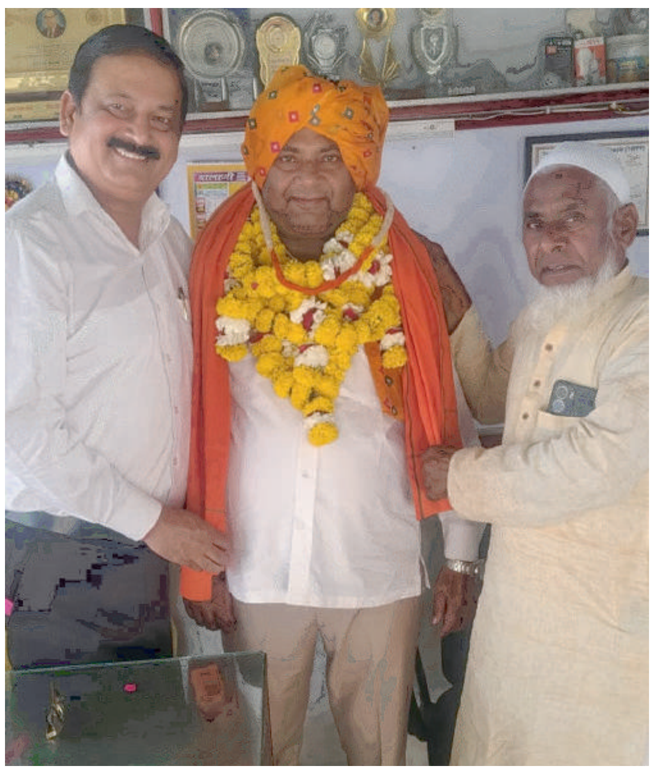

समय दूंगा। यही कारण है कि मैं समय से पूर्व अपनी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी एवं जन कल्याणकारी पार्टी है इसका सदस्य होने का मुझे गर्व है।

दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने रचा बड़ा षड्यंत्र : सौरभ भारद्वाज

मुख्य संवाददाता,/ सुषमा रानी

नई दिल्ली, पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 मई 2025 को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम के भीतर भाजपा समर्थित एक संस्था सीएआईटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के लगभग सभी बड़े-बड़े बाजारों जैसे सदर बाजार, चांदनी चौक, दरियागंज, खारी बावली आदि के व्यापारियों को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, रामवीर विधूड़ी, मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी शामिल हुई । सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कि दिल्ली के बड़े बड़े बाजार जैसे सदर, चांदनी चौक आदि बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले (congested) क्षेत्र बन गए हैं। हालात ऐसे हैं, कि इन बाजारों में सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। इसीलिए दिल्ली सरकार यह रणनीति बना रही है, कि इन बाजारों को यहां से कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है, तब से दिल्ली के बड़े-बड़े बाजारों के व्यापारियों में एक डर और हड़कंप मचा हुआ है, कि आखिर दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली के व्यापारियों के साथ कौन सा षड्यंत्र रचने जा रही है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ यह षड्यंत्र लगभग पिछले 3 साल से सन 2022 में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा की सन 2022 में भाजपा के नेता कुलजीत चहल ने दिल्ली के बाजारों के कुछ व्यापारियों की मीटिंग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कराई। यह बैठक हरियाणा भवन में आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली के बंजारों के व्यापारियों को इस बैठक में तरह-तरह के प्रलोभन दिए गए और बाजारों को हरियाणा में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया। सौरभ भारद्वाज ने अपनी बात को सत्यापित करते हुए बताया, कि इस षड्यंत्र के तहत सोनीपत में हरियाणा सरकार के एचएसआईआईडीसी द्वारा भागीरथ पैलेस और चांदनी चौक नमक बाजारों का निर्माण किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा क्योंकि उस समय पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो भाजपा के लिए ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2022 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ व्यापारियों की बैठक हुई थी, तो इन बाजारों के व्यापारियों ने उस समय दिल्ली की केजरीवाल सरकार से संपर्क कर यह बताया था, कि कोई भी व्यापारी हरियाणा जाने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि उस समय दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह तय किया था, कि हम दिल्ली के बाजारों का नवीनीकरण करेंगे और बाजारों की स्थिति में सुधार करके व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाएंगे। व्यापारियों की मांग पर केजरीवाल सरकार ने यह तय किया था कि हम दिल्ली के बाजारों को दिल्ली से बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने न केवल यह तय किया था, बल्कि इस श्रृंखला में दिल्ली के चांदनी चौक बाजार का नवीनीकरण और व्यवस्थाओं को बेहतर भी करके दिखाया। साथ ही साथ दिल्ली के अन्य बाजारों को भी व्यवस्थित करने और उनके नवीनीकरण के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 100 करोड रुपए आवंटित किया था।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के यह बड़े-बड़े बाजार दिल्ली की धरोहर हैं। इन बाजारों में जो व्यापारी बैठे हुए हैं, इनकी दुकान, इनका व्यापार दादा, परदादा के जमाने से चला आ रहा है। यह बाजार इन व्यापारियों के लिए मात्र व्यापार का साधन नहीं है, बल्कि इनके बुजुर्गों की निशानियां इन बाजारों से जुड़ी हैं। कोई भी दिल्ली का व्यापारी दिल्ली के बाजारों को छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहता। सौरभ भारद्वाज ने कहा, कि इन बाजारों का नवीनीकरण किया जा सकता है, व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बाजारों में व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय इन बाजारों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करके दिल्ली को और दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली के व्यापारियों और दिल्ली के बाजारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़े हैं और भाजपा की दिल्ली सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता और दिल्ली के व्यापारी इस फैसले के खिलाफ हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के बाजारों के संबंध में लिया गया अपना यह निर्णय वापस लेना होगा।

दिल्ली में 55 जगहों पर बजेगा युद्ध सायरन, एयरपोर्ट कॉलोनियों समेत कहां-कहां होगी मॉक ड्रिल?

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में दिल्ली बुधवार को अपनी बचाव तैयारियों को परखेगी। बड़े पैमाने पर होने वाली इस मॉक ड्रिल में प्रमुख स्थानों, एयरपोर्ट, कॉलोनियों, बाजारों, कार्यालय क्षेत्रों और स्कूलों को शामिल किया जाएगा। कुल 55 स्थानों पर शाम 4 बजे आपदा सायरन बजेगा।

यह अभियान दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की देखरेख में चलाया जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, डीडीए, एमसीडी, दिल्ली फायर सर्विस, जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड जैसी एजेंसियों के लोग तत्काल मदद पहुंचाने की भूमिका में होंगे।

650 स्कूलों में बच्चों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

लोगों को बचाने और उनकी मदद करने की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करीब दो हजार सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों और 1,200 आपदा मित्रों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों पर होगी। दिल्ली के 650 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को भी ब्लैकआउट और आपदा की स्थिति में बचाव के उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा

पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस अभियान के तहत बचाव की तैयारियों को परखने के आदेश दिए हैं और इसकी तारीख 7 मई तय की गई है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में हवाई हमले, एक साथ कई जगहों पर फायरिंग और सर्च एंड रेस्क्यू का

रिहर्सल इस मॉक ड्रिल में होगा।

दिल्ली के 15 पुलिस जिलों में पुलिस टीमों द्वारा सायरन बजाकर अभ्यास की शुरुआत की जाएगी। जिसके लिए पुलिस ने एक किलोमीटर तक ध्वनि प्रसारित करने वाले विशेष उपकरण (एलआरएडी) भी मंगवाए हैं। वहीं, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

मॉक ड्रिल के आयोजन की रूपरेखा तय

अधिकारियों ने बताया कि अगले दो सप्ताह तक पूरे शहर में चरणबद्ध तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राजधानी इस अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस संबंध में सचिवालय से लेकर मुख्य सचिव और संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और नागरिक सुरक्षा सहित अन्य एजेंसियों के कार्यालयों में सिलसिलेवार बैठकें हुईं, जिनमें मॉक ड्रिल के आयोजन की रूपरेखा तय की गई।

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 11 राजस्व जिलों में से प्रत्येक में पांच स्थानों - एक बाजार, एक बड़ी आवासीय कॉलोनी, एक स्कूल, एक सरकारी कार्यालय और एक अस्पताल - की पहचान की गई है, जहां यह अभ्यास किया जाएगा।

विशेष रूप से, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और खान मार्केट, आईजीआई एयरपोर्ट सहित नई दिल्ली के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एक अधिकारी के अनुसार इस बार ब्लैकआउट ड्रिल संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए नॉर्दर्न पावरग्रिड के साथ समन्वय की आवश्यकता है। हालांकि, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर ब्लैकआउट की स्थिति को लागू करने पर चर्चा की।

कानपुर नगर निगम में सीनियरों की उपेक्षा, नेता की कृपा से महत्वपूर्ण कामों को लेकर चर्चा में जूनियर एई

सुनील बाजपेई

कानपुर। आजकल यहां नगर निगम का एक एई यानी सहायक अभियंता चर्चा में है ,क्योंकि जितना काम करने वाला ,काम को जानने वाला और अपने साथ जितना उनके हित में काम करने वाला यह सहायक अभियंता (एई) है, उतना कोई भी अन्य सीनियर अधिकारी अभियंता आदि भी कदापि नहीं। इस चर्चित एई के समर्थक सूत्रों के मुताबिक यह नगर निगम का दुर्भाग्य कि इस एई यानी सहायक अभियंता के 'गुणों' को और उसकी 'काबिलियत' को बहुत देर से पहचाना गया। अगर उसकी इस काबिलियत उसकी इस योग्यता, उसकी इस कार्य दक्षता और इसी के साथ उसकी ईमानदारी को कानपुर में नियुक्ति यानी लगभग डेढ़ साल पहले पहचान लिया गया होता तो लाभ के हालात उनके पक्ष में और भी अच्छे होते जिन्होंने उसकी काबिलियत को अब पहचाना है।

समर्थक सूत्रों के मुताबिक इस सहायक अभियंता की विशेषताओं को पहचानने का श्रेय मुख्य रूप से एक बड़े नेता को ही जाता है। यह उनकी महानता है जो कि उन्होंने समय रहते इस ऐई की विशेषताओं को ना केवल पहचान लिया बल्कि नगर निगम का जो अधिकारी सक्षम है। उनसे इस एई को जोन के साथ ही मुख्य अभियंता का काम, पर्यावरण का काम ,सी एम ग्रेड का काम ,ए टू जेड प्लान का काम, स्मार्ट सिटी का काम, उद्यान अधिकारी का काम। यहां तक कि लगभग डेढ़ सौ करोड रुपए वाले 15 वें वित्त आयोग का भी काम इसी एई मतलब सहायक अभियंता के हवाले करवा दिया। जिसके बाद उसकी चर्चा के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र नजर आ रहा है। वह भगवान सूर्य ,जिन्हें दिवाकर,भास्कर भी कहते हैं। नगर निगम के भरोसे मंद सूत्रों के मुताबिक उपरोक्त जितने भी महत्वपूर्ण कार्य इस जूनियर अधिकारी अस्सिटेंट इंजीनियर के हवाले किए गए हैं , उससे प्रभावशाली नेता ने

यह साबित कर दिया है कि अपने को प्रमुख सचिव का खास बताने और बड़े अधिकारियों को ठेंगे पर रखने के लिए भी चर्चित इस ए ई को छोड़कर बाकी सीनियर इंजीनियर अयोग्य और बेईमान है।

इस ए ई के भरोसे मंद सूत्रों की नजर में यही वजह है कि एक आध को छोड़कर अधिकांश सीनियर अभियंता खाली बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह बात दीगर है कि

आरके सिंह जैसे अभियंता हल्के फुल्के भाग्यशाली भी माने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास केवल जॉन 6 का चार्ज है। इस तरह से उद्यान अधिकारी कृपा शंकर पाण्डेय पांडे के पास पदनाम तो है लेकिन वास्तविक रूप से उद्यान विभाग के काम पर कब्जा इस सहायक अभियंता यानी ए ई के पास बताया जाता है। अब जहां तक इस चर्चित सहायक अभियंता एई की उपलब्धियां का सवाल है। पर्यावरण और ए टू जेड का क्या हाल है ? जिससे अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, 15 वें वित्त आयोग के डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक बताए जाने वाले सीएम ग्रेड के कार्य अब तक शुरू हुए या नहीं ? अगर नहीं शुरू हुए तो क्यों और किस वजह से नहीं ? इन सब महत्वपूर्ण कार्यों का प्रभारी किसी जूनियर इंजीनियर को होना चाहिए या सीनियर को ? कुल मिलाकर यह अधिकारी भले ही जूनियर है लेकिन उसके आगे लगभग सारे सीनियर अधिकारी फेल हैं ,क्योंकि जितना अधिक प्रभावशाली यह सहायक अभियंता यानी एई है, उतना नगर निगम का कोई अन्य सीनियर अधिकारी भी नहीं। अगर आपको ठेका लेना है तो आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के साथ ही उनके पर्यायवाची नाम दिवाकर भास्कर और बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपैया का जाप करते हुए इस चर्चित एई की 'शर्त' पूरी कर दीजिए आपको मनचाहा लाभदायक ठेका भी अवश्य मिल जाएगा। और अगर यकीन ना हो तो जिनको ठेका मिल गया है या फिर मिल जाता है। इस ए ई के उन चहेते लोगों से पूछ लीजिए। कर्मचारी नेता अनिल कुमार, रामनारायण समुद्रे अनिल कुमार, समाजसेवी राजन तिवारी और आशीष मिश्रा आदि ने भी इस चर्चित ए ई से संबंधित उपरोक्त जानकारी की सत्यता की पुष्टि भरोसेमंद सूत्रों से बातचीत में करते हुए उसकी आय से अधिक लाखों करोड़ों की बताई जाने वाली चल - अचल ,नामी और बेनामी संपत्ति की जांच कराए जाने की भी मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। लेकिन प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों से मजबूत गठजोड़ के चलते इस ए ई के खिलाफ क्या वास्तव में कोई कुछ कर पाएगा। यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

नोएडा में मेट्रो के आगे कूदकर युवती ने दी जान, युवक के साथ पहुंची थी गोल्फ कोर्स स्टेशन

सुनील बाजपेई

नोएडा में एक युवती ने मेट्रो के आगे कूदकर जान दे दी। गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर हुई घटना। मृतक युवती की पहचान सिम्मी के रूप में हुई जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा अपडेट और नोएडा से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जागरण के साथ बने रहें।

नोएडा। नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वह युवक के साथ मेट्रो स्टेशन आई थी। मृतक युवती की पहचान 25 वर्षीय सिम्मी के रूप में हुई है। वह नोएडा में एक निजी कंपनी में जॉब करती थी। पुलिस मामले में जांच कर रही है। युवती के सुसाइड पर क्या बोली पुलिस? इस संबंध में नोएडा पुलिस ने बताया कि मंगलवार को थाना सेक्टर 39 क्षेत्रा अंतर्गत गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के सामने मेट्रो के आगे कूद कर युवती ने आत्महत्या कर ली। 25 वर्षीय युवती की पहचान सिम्मी पुत्री राजीव रंजन के रूप में हुई है। वह सलारपुर थाना सेक्टर 39 की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार, युवती के सुसाइड की सूचना पर थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, युवती के परिजनों को सूचित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के ट्रैक पर होने के कारण ब्लू लाइन (लाइन - 3) पर सेवाओं में देरी हुई। इसके अलावा अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य चल रही हैं।

मॉडलिंग की दुनिया में बिलासपुर छत्तीसगढ़ की दामिनी देवांगन का जलवा

*मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 बनी असम्भव कुछ भी नहीं, बशर्ते आप कोशिश करें : दामिनी

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर की रहने वाली दामिनी देवांगन ने गोवा के कैंडोलिम बीच स्थित होटल सोनैस्टा इन में आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट शो में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एस. एस. फाउंडेशन, भिलाई द्वारा किया गया, जिसकी ऑर्गेनाइज़र मिसेज शिखा साहू थीं। कार्यक्रम में बॉलीवुड सेलेब्रिटी महक चहल मुख्य अतिथि रहीं और ग्रूमिंग सेशन का नेतृत्व पुणे की ग्रूमर मिसेज पल्लवी कौशिक ने किया।

दामिनी इससे पहले जनवरी 2025 में मिस छत्तीसगढ़ विनर भी रह चुकी हैं। वे फिलहाल एमबीए के अंतिम वर्ष की छात्रा हैं और प्रोफेशन से फार्मासिस्ट व मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। दामिनी मॉडलिंग को अपने जुनून के रूप में देखती हैं और प्राइवेट जॉब के साथ-साथ मॉडलिंग को भी आगे बढ़ा रही हैं। दामिनी के पिता नारायण देवांगन शॉप चलाते हैं, माता गृहिणी हैं, दो छोटे भाई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जनवरी 2025 से प्रोफेशनल मॉडलिंग में कदम रखने वाली दामिनी को परिवार का पूरा सहयोग मिला है। उनका सपना है कि वे प्रोफेशनल रनवे मॉडल बनें, एड और ब्रांड

शूट्स करें और किसी प्रतिष्ठित ब्रांड की ब्रांड एंबेसडर बनें।

परिवार की जिम्मेदारी भी

दामिनी मध्यमवर्गीय परिवार से हैं और परिवार में बड़े होने की वजह से घर की जिम्मेदारी भी उन पर है। आत्मविश्वास से लबरेज़ दामिनी की उड़ान बड़ी ऊँची है। अपने जीवन में कुछ बड़ा कर गुज़रने की ललक उनके दिल व दिमाग में है। उनका कहना है कि अब तक किसी को अपना आदर्श मानकर मैने यह मिसाल क़ायम की है और मै चाहती हूँ कि लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनूं। लोगों के लिए रोल मॉडल बनूं। दामिनी का कहना है कि ज़िंदिगी में कोई भी चीज़ असम्भव नहीं हैं बशर्तें उसे पाने की कोशिश की जाए। उड़ान भरने के लिए सारा आकाश खुला है अपने सपनों को पूरा करने के लिए टूट पड़ें, जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी।

किसानों के खेतों की मिट्टी कैसे उगलेगी सोना? कृषि विभाग ने दिए आसान टिप्स

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि विभाग ने खेतों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के आसान उपाय बताए हैं। गर्मी में गहरी जुताई करके किसान कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कतार में बुवाई फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी पारंपरिक तकनीकों से लागत कम होगी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलेगा। इन तरीकों से जल वायु और मृदा प्रदूषण भी कम होगा।

ग्रेटर नोएडा। किसानों के लिए यह अच्छी सलाह है। गर्मी में खेतों की जुताई कर पैदावार बढ़ाएं। इससे मिट्टी सोना उगलेगी। रासायनिक खादों के तेजी से बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। गर्मी में गहरी जुताई करने से कीटों पर नियंत्रण होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा।

कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन

जिला कृषि रक्षा अधिकारी

विनोद कुमार ने ग्रीष्मकालीन खेती करने वाले किसानों को बेहतर उपज पाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती जैसे कतार में बुवाई, फसल चक्र, मिश्रित फसल और ग्रीष्मकालीन जुताई से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होगा।

इन तरीकों को अपनाने से जल, वायु, मृदा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। उन्होंने कीट और रोग नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों में भी परंपरागत तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। फसलों की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन जुताई खरीफ फसलों की तैयारी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ग्रीष्मकालीन जुताई मानसून आने से पहले जुलाई, मई-जून के महीनों में की जाती है।

खेत के ग्रीष्मकालीन जुताई से यह हैं लाभ

मिट्टी की संरचना में सुधार होगा। इससे जल धारण क्षमता बढ़ेगी और उपज में वृद्धि होगी।

खेत की कठोर परत टूट जाती है और पौधे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं।

खरपतवार और फसल अवशेष दबकर सड़ने से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उर्वरता बढ़ती है।

मिट्टी में छिपे कीट जैसे दीमक, सफेद ग्रब, कटवर्म बीटल आदि नष्ट हो जाते हैं। अगली फसल में कीटों का प्रकोप कम होता है।

गर्मी में जुताई से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और लाभकारी सूक्ष्म जीव पनपते और विकसित होते हैं।

भारत-पाक युद्ध की दस्तक ?- 54 वर्षों बाद 7 मई 2025 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र ने सिविल डिफेन्स मॉक ड्रिल के आदेश जारी किए

भारत की डिप्लोमेसी व सैन्य तैयारी, हाई लेवल मीटिंग्स, आतंकवादियों के खिलाफ रूस अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पाक घबराया– **एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ की नजरें भारत पर लगी हुई है कि भारत कब पाक़ के खिलाफ मिलट्री एक्शन शुरू करता है। हालांकि इसपर भारतीय नागरिकों की भी नज़रें लगी हुई है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब समय आ गया है कि पाक़ पर मिलिट्री कार्यवाही जल थल वायु जो किसी भी स्थिति में हो, शुरू करने की जरूरत है,परंतु मेरा मानना है कि अभी जो भारत सरकार उच्चस्तर पर रणनीति के तहत चल रही है, वह सही भी है क्योंकि युद्ध शुरू करने के पहले उसके लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स, नागरिकों पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय सोच सहयोग सहित अनेक कूटनीतिक, डिप्लोमेसी सहित अनेक रणनीतियां होती है,जिससे दुश्मन को आधा परास्त तो ऐसे ही कर दिया जाता है, बाकी बचाकुचा तीनों अंगों की सैन्य कार्रवाई से पूरा हो सकता है।5 मई 2025 को देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिविल मॉक ड्रिल के आदेश जारी कर दिए गए हैं जो सभी राज्योंकेंद्रशासित प्रदेशों को 7 मई 2025 को करने होंगे, इसके पहले पाक़ को घुटने टिकाने अनेक आदेश जारी किए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, इसी कड़ी में 5 मई 2025 कोही रूस के राष्ट्रपति ने भी संचार माध्यम से भारतीय पीएम से बात कर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई।अब सिविल मॉक ड्रिल आदेश को आधार बनाकर आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,भारत-पाक युद्ध की दस्तक ?54 वर्षों के बाद 7 मई 2025 को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र ने सिविल मॉक ड्रिल के आदेश जारी किए हैं।

साथियों बात अगर हम भारत- पाक युद्ध की संभावित दस्तक की करें तो, गृह मंत्रालय ने 1971 के बाद पहली बार 7 मई को देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं।पीएम द्वारा पिछले 7 दिनों में तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा सचिव से मुलाकातों के बाद सैन्य तैयारियों की समीक्षा की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की प्रतिक्रिया का समय, तरीका और लक्ष्य तीनों सेनाएं खुद तय करेंगी।पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।7 मई को कौन-कौन से राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।पाक से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जासके।हालांकि रविवारसोमवार रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट प्रैक्टिस की गई। इस दौरान गांवों और मोहल्लों में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद रही।दरअसल, 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार किसी भी संभावित खतरे से पहले तैयारी करना चाहती है।

साथियों बात अगर हम सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल को समझने की करें तो, (1) मॉक ड्रिल यानी एक तरह की ₹प्रैक्टिस₹ जिसमें हम यह देखतेहैं कि अगर कोईइमरजेंसी (जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला) हो जाए, तो आम लोग और प्रशासन कैसे और कितनी जल्दी रिएक्ट करता है (2) ब्लैकआउट एक्सरसाइज का मतलब है कि एक तय समय के लिए पूरे इलाके की लाइटें बंद कर देना। इसका मकसद यह दिखाना होता है कि अगर दुश्मन देश हमला करे,तो इलाके को अंधेरे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है।ड्रिल में होंगे ये प्रमुख कदम - (1) एयर रेड सायरन की टेस्टिंगः दुश्मन हमले के समय चेतावनी देने वाले सायरनों की जांच और एक्टिवेशन होगा। (2) सिविल डिफेंसट्रेनिंगः आम लोगों को सिखाया जाएगा कि वे हमले के वक्त कैसे सुरक्षित रहें। (3)

ब्लैकआउट की व्यवस्थाः हमले के वक्त रोशनी पूरी तरह बंद करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। (4) कैमो फ्लाज की तैयारीःदेश के महत्वपूर्ण प्लांट्स और ठिकानों को छिपाने की तकनीक अपनाई जाएगी। (5) इवैक्यूएशन प्लानः आपात स्थिति में लोगों को निकालने की योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास भी होगा।

साथियों बात अगर हम भारत पाक तनाव चरम परपहुंचने की करें तो,सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद है देश को किसी भी संभावित खतरे के लिए तैयार करना।ये ड्रिल देशवासियों को जागरूक करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।गृह मंत्रालय ने राज्यों को कई अहम निर्देश दिए हैं।सबसे पहले,हवाई हमले कीचेतावनी देने वाली सायरन की जांच की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत सतर्क हो सकें। इसके अलावा, आम नागरिकों और स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि हमले की स्थिति में खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। रात के समय ब्लैक आउट की प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा ताकि हवाई हमलों के दौरान शहरों की रोशनी दुश्मन को नजर न आए। महत्वपूर्ण इमारतों और ठिकानों को छिपाने के लिए छलावरण की तकनीक का इस्तेमाल होगा। साथ ही,आपातकाल में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए निकासी योजनाओं को अपडेट किया जा रहा हैं।

साथियों बात अगर हम पाक के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई की गूंज की करें तो, पहलगाम अटैक को पूरे दो हफ्ते हो गए हैं, आज 14 वां दिन है, इन 14 दिनों में सिर्फ बैठकें हुई हैं, बड़ी-बड़ी बैठकें, डिप्लोमेटिक एक्शन हुए हैं, पाक का पानी रोकने पर एक्शन हुआ, पाक का पैसा बंद करने पर भी बात हो रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 26 निर्दोष लोगों के हत्यारे पर सीधा हमला कब होगा, भारत पाक पर कब अटैक करेगा। भारत की सेना लाहौर, इस्लामाबाद का रुख कब करेगीइंडियन एयरफोर्स के जेट पाकिस्तान मिलिट्री के इंस्टॉलेशन को निशाना कब बनाएंगे,ये देश की मंशा है।देश यही चाहता है लेकिन ये कब होगा, ये कोई नहीं जानता।आज देश में लोग पूछ रहे हैं कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला क्यों नहीं लिया है, अगर आज सरकार की भाषा में कहें तो भारत बदला लेगा और जरूर लेगा। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदले में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या ये देरी तैयारियों की वजह से है और क्या भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है? हकीकत ये है कि अब तक भारत बिना हथियार चलाए पाकिस्तान के पसीने छुड़ा चुका है। हर मोर्चे पर घिर चुका पाकिस्तान बिना मार के रो रहा है। अब बस युद्ध का सायरन बजने ही वाला है और भारत ने अपने नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है, सबसे पहले बात उस सवाल की जिसका जवाब इस वक्त देश के 140 करोड़ लोग जानना चाहते हैं और वो सवाल है कि पाकिस्तान से बदला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इस वक्त तो फिलहाल बस देश में एक ही नैरेटिव चल रहा है कि जनता बदला चाहती है। देश वासियों का ये गुस्सा जायज भी है क्योंकि आतंकवादियों ने बहुत बड़ी चुनौती दी है, धर्म पूछ- पूछकर गोली मारी है इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि इस बार कार्रवाई ऐसी हो ताकि पाकिस्तान के आंतकवादियों की नहीं बल्कि उनकी फौज की भी सात पुश्तें याद करें, देशवासी इसलिए भी अधीर हो रहे हैं क्योंकि पिछली दोनों बार यानी कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में इस वक्त तक स्ट्राइक हो चुकी थी इसीलिए ये इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर इस बार की स्ट्राइक कब होगी।पिछली बार 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था,भारतीय सेना ने 10 दिनों के बाद 28 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी।सरहद पार सेना ने 38 आतंक वादी और 2 पाक सैनिकों को सर्जिकल स्ट्राइक में मार गिराया था।इसीतरह से 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, 12 दिन के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी।आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए थे।यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि अबकी बार तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया है.

साथियों बात अगर हम युद्ध के लिए धैर्य की आवश्यकता की करें तो, सरकार तो साफ कह रही है कि बदला तो होकर रहेगा लेकिन बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखना होगा और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है,लेकिन युद्ध के लिए बहुत कुछ सोचकर चलना पड़ता है, सेना को हर तरह की तैयारी करनी पड़ती है,सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो फिर वो जीतने के लिए होगी, हारने के लिए, सेना अगर युद्ध की तैयारी करेगी तो हर एंगल को ध्यान में रखेगी, वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलेगी। पाक के साथ वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि युद्ध आरपार का होगा और फिर ऑप्शन न्यूक्लियर वॉर का भी है,युद्ध की स्थिति में सेना को हर फ्रंट देखना होगा। युद्ध अगर होगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं होगा इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी होगा यानी कि हम राजस्थान और गुजरात की भी बात कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो इंटरनेशनल खेमेबंदी कैसी होगी यानी कि कौन सा देश किसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कौन आएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का साथ चीन देता है, तो ये भी देखना होगा कि अगर युद्ध हुआ तो क्या चीन भारत पर हमला कर सकता है. ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि ये सारे फैक्टर देखने के बाद ही भारत कोई कार्रवाई करेगा।

अतः अगर हम अपरोध पूरे विवरण का अध्ययन करें इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत-पाक युद्ध की दस्तक ?- 54 वर्षों बाद 7 मई 2025 को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र ने सिविल मॉक ड्रिल के आदेश जारी किए।भारत को पाक़ के खिलाफ मिलट्री एक्शन की दरकार है- पूरी हुई रणनीतिक तैयारी,अब एक्शन की बारी।भारत की डिप्लोमेसी व सैन्य तैयारी, हाई लेवल मीटिंग्स,आतंकवादियों के खिलाफ रूस अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पाक घबराया?

स्कोडा काइलाक पहले से ज्यादा हुई किफायती, टॉप वेरिएंट की कीमत 46,000 रुपये घटी

परिवहन विशेष न्यूज

स्कोडा काइलाक की कीमतों में संशोधन किया गया है। इसे टॉप वेरिएंट की कीमतों में एक तरफ जहां कटौती की गई है वहीं इसके बेस वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। यह भारत में बिकने वाली स्कोडा की सबसे किफायती मॉडल होने के साथ ही सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। आइए जानते हैं कि Skoda Kylaq की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी और कमी हुई है?

नईदिल्ली। Skoda Kylaq को भारत में दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। अब इसके कुछ वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी तो कुछ वेरिएंट की कीमतों में कटौती की गई है। स्कोडा ने मई 2025 के लिए काइलैक की कीमतों में संशोधन किया है। आइए जानते हैं कि किस वेरिएंट की कीमत में कितना उतार-चढ़ाव देखने के लिए मिला है।

इन वेरिएंट की बढ़ी कीमत

Skoda Kylaq को भारत में 7.89 लाख रुपये से लेकर 14.40 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआती कीमत अवधि को अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बेस क्लासिक ट्रिम की कीमत में 36,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब इसके मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले इस ट्रिक की कीमत 8.25 लाख रुपये हो गई है। इसके साथ ही सिग्नेचर MT और AT वेरिएंट की कीमत में 26,000 रुपये और 36,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

इन वेरिएंट की घटी कीमत

Skoda Kylaq की आने वाली टॉप वेरिएंट की कीमत में कटौती की गई है। इसके सिग्नेचर+ MT और AT वेरिएंट में क्रमशः 15,000 रुपये और 5,000 रुपये की कटौती की गई है। वहीं, इसके टॉप प्रेस्टीज ट्रिम की कीमत में क्रमशः 46,000 रुपये और 41,000 रुपये कम किए गए हैं।

अब तक कितनी बिकी Skoda Kylaq?

Kylaq की बिक्री से कंपनी को काफी फायदा हुआ है। मार्च 2025 में काइलैक की 5,327 यूनिट की बिक्री हुई थी, जिससे स्कोडा को पिछले 25 वर्षों में भारत में 7,409 यूनिट की सबसे अधिक मासिक बिक्री मिली। इसकी डिलीवरी जनवरी 2025 से शुरू हुई है।

भारत में इन गाड़ियों से मुकाबला

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Nexon, Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV3XO जैसी गाड़ियों से देखने के लिए मिलता है। वहीं, यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कोडा की कार होने के साथ ही कंपनी की सबसे किफायती मॉडल भी है।

नए रंगरूप में लॉन्च हुआ यामाहा ऐरॉक्स, इंजन को मिला बड़ा अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

2025 यामाहा ऐरॉक्स का S वर्जन भारत में लॉन्च हो गया है। इसे दो नए कलर के साथ ही इंजन को अपडेट किया गया है। इसका इंजन अब OBD-2B के अनुरूप हो गया है। वहीं इसे रेसिंग ब्लू और आइस फ्लूओ वर्मिलियन कलर मिले है जो इसे पहले से ज्यादा बेहतरीन लुक देते हैं। यह कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है।

नई दिल्ली। 2025 यामाहा ऐरॉक्स 155 संस्करण एस को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे नए कलर के साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इसके साथ ही यामाहा ने अपने इस स्कूटर को OBD-2B कंप्लायंट इंजन से लैस कर दिया है। आइए जानते हैं कि 2025 Yamaha Aerox Version S को भारत में किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है और इसे क्या नया मिला है?

मिले दो नए कलर

Yamaha Aerox 155 को दो नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है, जो रेसिंग ब्लू और आइस फ्लूओ वर्मिलियन है। इसमें दिया गया रेसिंग ब्लू कलर स्कीम एप्रन, रिम्स और बॉडी पैनल पर आइकॉनिक यामाहा ब्लू की फिनिश को दिखाता है। इसे मिले दोनों नए कलर वास्तव में काफी बेहतरीन दिखाई देते हैं। यह कलर ही इसे Yamaha की स्पोर्ट्स बाइक की तरह लुक देता है।

आइस फ्लूओ वर्मिलियन में एप्रन और बॉडी पैनल पर काले और सफेद रंग का कॉम्बो दिया गया है। इसके साथ ही इसपर लाल रंग की Aerox ब्रांडिंग भी गई है। इसके स्कूटर के रिम पर भी लाल रंग दिया गया है। यह कलर थोड़ा चमकीला है और उन लोगों को काफी पसंद आएगा, जो काफी अलग दिखने वाला स्कूटर की तलाश में रहते हैं।

कैसा है इंजन?

2025 Yamaha Aerox 155 Version S के इंजन को भी अपडेट किया गया है। इसका इंजन अब OBD-2B के अनुरूप हो गया है। इसके अलावा स्कूटर के इंजन में कई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें अभी भी उसी 155cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 15PS की पावर और 13.9Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन-रियर शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। इसमें ट्यूबलेस टायर के साथ 14-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। स्कूटर में ब्रेकिंग के लिए आगे की तरफ 230mm डिस्क और पीछे की तरफ 130mm ड्रम ब्रेक दिया दिया गया है।

फीचर्स

2025 Yamaha Aerox 155 Version S को स्मार्ट की और कीलेस इग्निशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और सिंगल-चैनल ABS जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस किया गया है।

कीमत

2025 Yamaha Aerox 155 Version S को भारत में 1,53,430 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है, जो पिछले मॉडल से 1,730 रुपये महंगी है। भारत में इसका मुकाबला मैक्सी-स्टाइल स्कूटर जैसे अप्रिलिया SXR 160 और हीरो जूम 160 से देखने के

महिंद्रा ने बताया फ्यूचर प्लान, इस साल 15 अगस्त को नया प्लेटफॉर्म तो 2026 में लॉन्च करेगी 5 गाड़ियां

इस साल 15 अगस्त को महिंद्रा अपनी SUV के लिए नया प्लेटफॉर्म पेश करेगी। यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर महिंद्रा की आने वाली सभी गाड़ियां पेट्रोल डीजल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को बनाया जाएगा। इसे मोनोकॉक प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। वहीं कंपनी अगले साल 2026 में कंपनी 5 गाड़ियों को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं जिसमें महिंद्रा थार फेसलिफ्ट और महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट होंगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। साल 2024 में Mahindra की Thar Roxx, Mahindra XUV 3XO, Mahindra BE 6 और Mahindra XEV 9e को लॉन्च किया गया था। अब कंपनी ने खुलासा किया है कि वह 15 अगस्त 2025 को नया एसयूवी प्लेटफॉर्म पेश करेगी। इसके साथ ही कंपनी अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है। आइए जानते हैं कि Mahindra का नया एसयूवी प्लेटफॉर्म कैसा होगा और कौन-सी गाड़ियां लॉन्च होने वाली है।

नए प्लेटफॉर्म पर बनेगी Mahindra की गाड़ियां

महिंद्रा इस साल के 15 अगस्त को नया प्लेटफॉर्म पेश करने वाली है। यह प्लेटफॉर्म कैसा होगा इसके बारे में कंपनी की तरफ से कोई डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मोनोकॉक प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे पावरट्रेन ऑप्शन को सपोर्ट कर सकता है। महिंद्रा ने पुणे के चाकन में एक नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है जो नए प्लेटफॉर्म पर आधारित प्रति वर्ष 1.2 लाख मॉडल का निर्माण करेगा।

कौन-सी गाड़ियां होंगी लॉन्च?

महिंद्रा 2030 तक भारत में 7 नई ICE SUV और 5 EV लाने की योजना बनाई है। इसमें से 3 ICE SUV और 2 EV को अगले साल 2026 में लॉन्च करेगी। महिंद्रा ने पुष्टि की है कि ICE उत्पादों में से 2 मिड-साइकिल फेसलिफ्ट होने वाले हैं, जिसमें महिंद्रा थार फेसलिफ्ट और महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट होंगी। इतना ही नहीं महिंद्रा बोलेरो को भी अगले साल की शुरुआत या इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

हुंडई एक्सटर के दो सबसे किफायती वेरिएंट लॉन्च, सनरूफ समेत कई बेहतरीन फीचर्स से है लैस

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई एक्सटर के सबसे किफायती वेरिएंट को लॉन्च किया गया है। इन दोनों वेरिएंट में भर-भर के फीचर्स दिए गए हैं। इन दोनों ट्रिम का नाम S Smart और SX Smart है। इन दोनों में ही कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। S Smart वेरिएंट में तो सिंगल-पैन सनरूफ भी दिया गया है जिससे यह एक्सटर की सबसे किफायती मॉडल हो गई है।

नईदिल्ली। हुंडई एक्सटर को दो नए ट्रिम के साथ अपडेट किया गया है। इसे एस स्मार्ट और एसएक्स स्मार्ट ट्रिम मिले है। इसके हाई ट्रिम से कुछ फीचर्स को कम किया गया है और इसके अलावा ऑप्शनल इक्यूमेंट को शामिल किया गया है। इन दोनों ट्रिम को पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि Hyundai Exter इन दोनों ट्रिम में क्या फीचर्स दिए गए हैं और इन्हें किन फीचर्स से साथ लैस किया गया है?

Hyundai Exter S Smart

यह मौजूदा S ट्रिम पर बेस्ड है, इसमें सिंगल-पैन सनरूफ दिया गया है, जो पहले एस+ में मिलती था। इसमें एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप, एलईडी टेल लैंप, टीपीएमएस, 15-इंच स्टील व्हील और रियर एसी वेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसे भारत में 7.69 लाख रुपये की एक्स-शोरूम की कीमत में लॉन्च किया गया है।

Hyundai Exter SX Smart

इसमें पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप फीचर के साथ कीलेस एंट्री भी दी गई है। इसके अलावा, प्रोजेक्टर हेडलैंप, रियर पार्किंग कैमरा, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री और शार्क फिन एंटीना भी इस ट्रिम में दिया गया है। इसे भारत में 8.16 लाख रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है।

नए वैकल्पिक उपकरण

S Smart और SX Smart ट्रिम अगर आप वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ एक बड़ा 9.0-इंच टचस्क्रीन और रियर कैमरा जैसे फीचर को शामिल करवाना चाहते हैं तो आप इन्हे 14,999 रुपये में शामिल करवा सकते हैं। इनपर कंपनी 3 साल की वारंटी भी दे रही है। मानक के तौर पर, Exter के सभी वेरिएंट में केवल 8.0-इंच मिलता है। Hyundai ने Exter पर ISOFIX एंकर पॉइंट भी मानक बनाया है।

कैसा है Hyundai Exter का इंजन?

Exter में 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 83hp की पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स दोनों के साथ पेश किया जाता है। वहीं, इसका CNG इंजन 69hp की पावर और 95.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाता है। इसमें हुंडई का नया डुअल सीएनजी सिलेंडर टैंक सेटअप भी दिया गया है।

सैंट्रो से लेकर आयोनिक5 तक हुंडई ने भारत में पूरे किए 29 साल, 12.7 मिलियन कारों की हुई बिक्री

परिवहन विशेष न्यूज

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता ने छह मई को देश में 29 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच निर्माता की ओर से कितने वाहनों की बिक्री की गई है। कितनी यूनिट्स को भारत से दुनिया के अन्य देशों में भेजा गया है। भविष्य में निर्माता की क्या तैयारियां हैं। आइए जानते हैं।

नईदिल्ली। भारतीय बाजार में कई विदेशी वाहन निर्माता अपने वाहनों को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाती हैं। इसी क्रम में साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई भी कई वाहनों को ऑफर करती है। निर्माता ने देश में 29 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान किन प्रमुख कारों को भारत में ऑफर किया गया। भविष्य के लिए हुंडई क्या तैयारी कर रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हुंडई ने पूरे किए 29 साल

भारतीय बाजार में साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई ने 29 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान निर्माता की ओर से कई सेगमेंट में कई कारों को ऑफर किया गया। 29 साल में हुंडई की ओर से 12.7 मिलियन यूनिट्स की बिक्री की गई है। इनमें से 3.7 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स को भारत में बनाकर 150 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी किया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात

इस मौके पर हुंडई मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक अनसू किम ने कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण और वाणिज्य के केंद्र में रखते हुए, हुंडई ने 29 साल पहले आपसी प्रगति के दृष्टिकोण के साथ देश के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। आज, हम इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम कितनी दूर आ गए हैं - न केवल स्मार्ट मोबिलिटी समाधान प्रदान करना, बल्कि एक ऐसा भविष्य जो नवाचार, स्थिरता और हमारे ग्राहकों के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। 'मानवता के लिए प्रगति' के हमारे वैश्विक दृष्टिकोण से निर्देशित, एचएमआईएल समाज में सार्थक योगदान करते हुए उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तन को आगे बढ़ाता रहेगा।

किन कारों को भी किया था ऑफर

हुंडई ने छह मई 1996 को भारत में अपने सफर की शुरुआत की थी। इसके बाद 1998 में निर्माता की ओर से Hyundai Santro कार को देश में ऑफर किया गया था। इसके अलावा निर्माता की ओर से 1999 में सेडान कार के तौर पर Hyundai Accent, 2001 में Hyundai Sonata, 2003 में Hyundai Terracan, 2004 में Elantra और Getz, 2010 में Santa Fe, 2011 में Eon, 2014 में Xcent और 2019 में Kona Electric जैसी कारों को ऑफर किया था।

अभी होती है इनकी बिक्री

2005 में Tucson, 2006 में Verna, 2007 में Grand Nios i10, 2008 में i20, 2015 में Creta, 2019 में Venue, 2020 में Aura, 2021 में Alcazar, 2023 में Exter और Ioniq5 के साथ ही 2025 में Creta Electric की बिक्री की जा रही है।

ये है भविष्य की योजनाएं

निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 2025 की चौथी तिमाही में महाराष्ट्र के तालेगांव में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा हाल में ही निर्माता की ओर से 1500 करोड़ रुपये चेन्नई की फैसिलिटी को अपडेट करने के लिए आवंटित किए हैं।

दुनिया भर में आ सकती है चीनी माल की बाढ़

प्रो. अश्वनी महाजन

अब जब भारत दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है, तो वह चीन से डंपिंग के किसी भी नए दौर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके आत्मनिर्भर भारत के सपने को खतरे में डाल सकता है'...

हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा के एक सप्ताह से भी कम समय में, 8 अप्रैल 2025 को 75 देशों पर अपने पारस्परिक टैरिफ को रोक दिया, लेकिन इस रोक में एकमात्र अपवाद था चीन, जिस पर ट्रम्प ने पहले 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसे हम दंडात्मक टैरिफ भी कह सकते हैं, क्योंकि चीन ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा पारस्परिक टैरिफ का जवाब देने का विकल्प चुना है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने पोस्ट में ट्रम्प ने कहा, 'चीन ने विश्व के बाजारों के प्रति जो सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 125 फीसदी कर रहा हूं। उम्मीद है कि निकट भविष्य में किसी समय चीन को एहसास होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों को लूटने के दिन अब टिकाऊ या स्वीकार्य नहीं हैं।' हालांकि, अमेरिका को छोडक़र भारत समेत किसी भी देश ने चीन पर टैरिफ नहीं बढ़ाया है, लेकिन अधिकांश देश, चीन द्वारा की जाने वाली डंपिंग से चिंतित हैं, जिससे उनके घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। डंपिंग का मतलब है कम दामों पर सामान बेचना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में डंपिंग तब होती है, जब कोई देश या कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेशी बाजार में कम कीमत पर उत्पाद का निर्यात करती है। डंपिंग को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दुरुपयोग माना जाता है। चीन ने डंपिंग की इस कला में महारत हासिल कर ली है, इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका उद्देश्य आयात करने वाले देशों के घरेलू उद्योग को खत्म करना है और एक बार जब कोई देश चीनी सामग्रियों पर निर्भर हो जाता है, तो फिर उसका शोषण शुरू हो जाता है। सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) का मामला चीनी डंपिंग और शोषण के जीते जागते उदाहरण हैं।

2004 के बाद, पेनिसिलिन जी और फोलिक एसिड सहित कई प्रकार की एपीआई को भारतीय बाजारों में बेहद कम कीमतों पर डंप किया गया। इस खेल में न केवल भारतीय एपीआई उद्योग को खत्म कर दिया गया, बल्कि देश की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया गया। मार्च में, भारत ने घरेलू उद्योगों को चीनी डंपिंग से बचाने के लिए चार चीनी वस्तुओं- सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमीनियम पन्नी और ट्राइक्लोरो आइसोसायन्यूरिक एसिड पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया था। एंटी-डंपिंग शुल्क 276 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1732 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक है और यह पांच साल के लिए है, जबकि एल्यूमीनियम पन्नी पर छह महीने का अस्थायी शुल्क लगाया गया है। इससे पहले 2024 में ही, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा दायर एंटी-डंपिंग जांचों में से 79 प्रतिशत चीनी उत्पादकों के खिलाफ दायर की गई थीं। यह ध्यान देने योग्य है कि डीजीटीआर भारत में व्यापार उपायों की जांच और सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, जो अन्य उपायों के साथ-साथ डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की भी सिफारिश करता है। चीन पहले से कहीं ज्यादा डंप क्यों करेगा? कारण यह है कि अमेरिकी टैरिफ के बाद, चीन के लिए अमेरिका को इतनी आसानी से निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चीन निश्चित रूप से अपने उत्पादों को अन्य बाजारों में डंप करने के लिए मजबूर होगा। सर्वप्रथम चीन के पास बहुत अधिक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जिससे अधिशेष उत्पादन होता है। कुछ बाजारों में बेचने की क्षमता, चीन को अन्य बाजारों में समान सामग्री डंप करने के लिए मजबूर करती है। चीन का ध्यान हमेशा निर्यात आधारित विकास पर रहा है, जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त है। दूसरे, चीनी कंपनियों को अन्य रूपों में सब्सिडी और सरकारी सहायता मिलती है, जिससे वे अपने उत्पादों को कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर बेच पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारी सब्सिडी बाजार की कीमतों को विकृत करती है और अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। तीसरे, व्यापार तनाव भी वैकल्पिक बाजारों पर किसी तरह नियंत्रण करने के चीनी खेल का हिस्सा है। चीनी डंपिंग को लेकर आशंकाएं बेवजह नहीं हैं।

अतीत में, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जब चीन ने भारत समेत विदेशी बाजारों में डंपिंग की अनैतिक प्रथा अपनाई। अतीत में, हमारा एपीआई उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम उद्योग, कपड़ा और परिधान उद्योग, खिलौना उद्योग और कई अन्य उद्योग चीनी डंपिंग का शिकार रहे हैं। इन उद्योगों की कई विनिर्माण इकाइयां चीनी डंपिंग के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। और सरकार के ठोस प्रयासों के बावजूद ये उद्योग चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा की छाया से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि भारत सरकार का दावा है कि वह वैश्विक बाजारों में उभरती स्थितियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन उद्योग चीन द्वारा संभावित डंपिंग प्रयासों से सभी चिंतित हैं। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिका लंबे समय से चीनी आयात पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन को अपने निर्यात को अन्य तरीकों से बदलने का कोई मौका न देने के उद्देश्य से ठोस प्रयास किए गए हैं, ताकि ट्रंप के टैरिफ से बचा जा सके। इस संदर्भ में अमेरिकी सीनेट ने दो विधेयक पेश किए हैं, नीदर परमानेंट नॉर नार्मल ट्रेड रिलेशंस अधिनियम (पीएनटीआर अधिनियम) और एक्सिंग नॉन मार्केट टैरिफ इवेजन एक्ट (एएनटीई अधिनियम)। पहला पीएनटीआर चीन से आयात पर केंद्रित है और दूसरा एएनटीई अन्य देशों में माल का उत्पादन करने वाली चीनी फर्मों को लक्षित करता है। जबकि, पीएनटीआर अधिनियम चीन से सीधे आने वाले माल को प्रतिबंधित करेगा और एएनटीई अधिनियम वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में चीनी स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों से आने वाले माल को प्रतिबंधित करेगा। इसलिए नए कानूनों के माध्यम से अमेरिका उन सभी संभावित माध्यमों को बंद करने की कोशिश कर रहा है जिनके माध्यम से चीन अमेरिका में अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भारत ने डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत उपलब्ध कई व्यापार उपायों का उपयोग किया है, जिसमें एंटी-डंपिंग शुल्क और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। भारत द्वारा लगाए गए अधिकांश एंटी-डंपिंग शुल्क चीन पर थे। भारत द्वारा चीनी डंपिंग को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों के बावजूद, चीनी आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, अप्रैल से फरवरी के बीच के पहले 10 महीनों में, चीन से भारत का आयात एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 10.4 प्रतिशत बढक़र 103.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दूसरी ओर, चीन को निर्यात 15.7 प्रतिशत घटकर 12.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। इससे जाहिर तौर पर चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है। यह डीजीटीआर की सिफारिश पर भारत द्वारा अपनाए गए एंटी-डंपिंग उपायों की लंबी सूची के बावजूद है। चीनी डंपिंग को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। लंबे समय से चीन से आयात भारत की विनिर्माण यात्रा को प्रभावित कर रहा है और विनिर्माण, जो 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 19.6 प्रतिशत प्रदान करता था, 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद में 14.27 प्रतिशत का योगदान देगा। यह भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए खतरे की घंटी है। अब जब भारत दुनिया के लिए विनिर्माण केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है, तो वह चीन से डंपिंग के किसी भी नए दौर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके आत्मनिर्भर भारत के सपने को खतरे में डाल सकता है। हमें चीन को भारतीय बाजारों में अपने माल की डंपिंग के अनैतिक और अवैध तरीकों का उपयोग करने से रोकने के लिए अपनी प्रशासनिक मशीनरी को सुव्यवस्थित करना होगा।

बड़े बदलावों का संकेत है जाति जनगणना

इस जनगणना का कार्य समाप्त होते ही 2027 में देश के सात राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन राज्यों में देश का राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी दल अपनी जीत सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा जातीय जनगणना देश में 2026 में होने वाले पुनर्सीमांकन के कार्य को भी प्रभावित करेगी। यह पुनर्सीमांकन भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रयोग में लेकर किया जाएगा। पुनर्सीमांकन भी देश की राजनीतिक तस्वीर में बदलाव लाता है, लेकिन जब जातीय जनगणना को आधार बनाकर यह पुनर्सीमांकन का कार्य किया जाएगा तो इससे यह बदलाव काफी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है',...

यूं तो भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास काफी पुराना है और इस तरह की जनगणना भारत के औपनिवेशिक काल में भी की जाती थी। भारत की आजादी से पहले आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना की गई थी। आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना में जाति से संबंधित कोई भी जानकारी देशवासियों से नहीं ली गई थी। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में सात जनगणनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये जनगणनाएं जाति आधारित नहीं रही। इन जनगणनाओं में अन्य मूलभूत जानकारियों के अलावा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती थी क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भारत का संविधान आरक्षण की व्यवस्था करता है। इन दोनों श्रेणियों के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं और लोकसभा से लेकर राज्यों की विधानसभाओं तक आरक्षण का प्रावधान है। संविधान में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने के कारण ही भारत की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस बार केंद्र सरकार ने 2025 में होने वाली जनगणना को जातिगत जनगणना का नाम दिया है अर्थात यह जनगणना अब जाति आधारित होगी और इसमें सभी जातियों के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे।

इस जनगणना में सबसे बड़ा रोमांच अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों की जनगणना होने से है। यह माना जाता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या देश में आधी जनसंख्या के आसपास है। एक अनुमान के अनुसार यह आबादी 52 प्रतिशत तक हो सकती है। 1980 में मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई थी। दस सालों तक मंडल आयोग की इस सिफारिश पर किसी भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। फिर 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी थी और 13 अगस्त 1990 को इसके संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। उस समय इसके विरोध में सामान्य वर्ग ने इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया था। कई महीनों तक इसके विरोध में पूरे भारत में हड़तालें और प्रदर्शन हुए थे। अब क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में तो आरक्षण मिल चुका है, तो क्या इस जातिगत जनगणना को आधार बनाकर इस श्रेणी को लोकसभा और विधानसभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी? यदि ऐसा हो जाता है तो यह जनगणना देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। केंद्र सरकार द्वारा अचानक जातिगत जनगणना की घोषणा करना हर किसी को हैरानी में डालने वाली है। जातिगत जनगणना को लेकर देश की संसद के दोनों सदनों में न केवल भाजपा और कांग्रेस में तीखी बहस हो चुकी है, बल्कि कई प्रकार की तल्ख टिप्पणियां भी इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर कर चुकी हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी देश में जातिगत जनगणना के लिए अपनी आवाज बुलंद करते देखे गए थे। जब कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तो केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट रूप से रखते हुए जातिगत जनगणना करवाने के लिए साफ इनकार कर दिया था तो फिर एकदम से केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर यू-टर्न क्यों ले लिया। इसमें कोई संशय नहीं है कि सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय बड़े सोच-विचार के बाद ही लिया है, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और यह देश में बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की आधारशिला रखने की ताकत रखता है। भले ही सरकार जातिगत जनगणना को देश के नीति निर्माण के लिए उपयोगी बता रही है और कांग्रेस इससे पिछड़ों को उनके अधिकार देने की बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों के अपने हित भी छुपे हुए हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद देश में पहले से मौजूद जातिगत विभाजन और गहरा हो सकता है और इससे सामाजिक स्तर पर कई और चुनौतियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन इन सबसे बढ़ कर इस जातिगत जनगणना और इसके समय को देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में पडऩे वाला है।

इस जनगणना का कार्य समाप्त होते ही 2027 में देश के सात राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन राज्यों में देश का राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सभी दल अपनी जीत सुनिश्चित करने का भी प्रयास करेंगे। इसके अलावा जातीय जनगणना देश में 2026 में होने वाले पुनर्सीमांकन के कार्य को भी प्रभावित करेगी। यह पुनर्सीमांकन भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रयोग में लेकर किया जाएगा। पुनर्सीमांकन भी देश की राजनीतिक तस्वीर में बदलाव लाता है, लेकिन जब जातीय जनगणना को आधार बनाकर यह पुनर्सीमांकन का कार्य किया जाएगा तो इससे यह बदलाव काफी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है।

सेना को खुली छूट

प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, आतंकियों और उनके आकाओं पर प्रहार करने की सेना को खुली छूट दे दी है। हमले का तरीका, जगह, लक्ष्य और समय सेनाएं ही तय करेंगी। प्रधानमंत्री ने देश की सेनाओं की क्षमताओं पर विश्वास जताया है। इतना जरूर स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। कश्मीर में ही उरी और पुलवामा आतंकी हमलों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले की अंतिम स्वीकृति प्रधानमंत्री से जरूर ली गई थी। प्रधानमंत्री ने बीते दो दिनों में दो बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन बैठकों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे, लेकिन निर्णायक बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री के सामने संभावित हमलों के प्रारूप और रोडमैप रखे गए होंगे! अंततः सेना को स्वतंत्र छूट दी गई। बुधवार, 30 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी, राजनीतिक और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समितियों की बैठकों में भी व्यापक विमर्श किया गया। कैबिनेट की पूरी बैठक भी की गई। अब सर्वोच्च स्तर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत ने पहलगाम नरसंहार का बदला लेना तय कर लिया है। तीनों सेना प्रमुखों के प्रारूपों में जो संशोधन जरूरी लगे होंगे, वे कैबिनेट की बैठकों में कर लिए गए। अब हमारी सेनाओं का आक्रामक प्रहार क्या होगा, यह उसी पल ही सामने आएगा, जब हमला किया जाएगा। भारत अपनी तरफ से युद्ध का आगाज करने नहीं जा रहा है। जो आतंकवाद के चेहरे हैं, निशाने पर सिर्फ वही होने चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ अपने लंबे, सैन्य अनुभवों के आधार पर आकलन कर रहे हैं कि आतंकियों के साथ-साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, वहां की फौज और सेना प्रमुख जनरल मुनीर हमारी सेनाओं के निशाने पर हो सकते हैं।

ये ही आतंकवाद का क्रमबद्ध सिलसिला हैं। सेना के ऑपरेशन जमीन और हवा के अलावा समंदर से भी किए जा सकते हैं। हमारी सेनाओं ने दुश्मन का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया होगा! हमारी सेनाओं के निशाने पर पाकिस्तान के 30 से ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जिन्हें सेनाएं मिसाइल हमलों में ही उड़ा सकती हैं। हमारी सेनाओं के पास ऐसे भी अस्त्र हैं, जिन्हें भारत की सीमा में रहते हुए भी छोड़ा जा सकता है। वे वाकई बेहद विध्वंसक हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सैन्य ऑपरेशन व्यापक और बहुध्रुवीय हो सकता है। बहरहाल सेना जो भी करेगी, पूरी दुनिया के सामने होगा, लेकिन एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि यह देश के एकजुट रहने का वक्त है। यह विवादास्पद, घटिया और मानहानि वाले पोस्टर पोस्ट करने का वक्त नहीं है। यह देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का भी समय नहीं है। हां, हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस आग्रह को समर्थन देते हैं कि संसद का एकदिनी विशेष सत्र बुलाया जाए और पाकिस्तान, आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। ऐसे विशेष सत्र 'निर्भया कांड' के बाद भी बुलाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नया विचार सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर सैन्य रणनीति का खुलासा बिल्कुल न करें। विपक्ष से भी हमारी अपेक्षाएं हैं कि वे फिजूल का दबाव सरकार पर न डालें। एक राष्ट्र के तौर पर, संसद के जरिए, आतंकवाद और पाकिस्तान की भूमिका को पुरजोर बेनकाब करें। बेशक दुनिया भी हमारी संसद से गूंजने वाले हुंकारों को सुनेगी। यदि सरकार संसद का सत्र नहीं बुलाती है, तो कमोबेश अभी उसे सियासत का आधार न बनाएं। भारत को पलटवार कर प्रतिशोध लेने दें, पीड़ित परिवारों को कुछ तसल्ली मिलने दें। देश सामान्य हो जाएगा, तो सरकार का विरोध जायज होगा।

आतंक पर हमला, तो युद्ध

प्रधानमंत्री मोदी और वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की मुलाकात हुई। इससे एक दिन पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी प्रधानमंत्री से मिले थे। सेना प्रमुखों की प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकातें सामान्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री इन मुलाकातों से पहले 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक बैठक कर चुके थे। उसी में सेनाओं को प्रहार का तरीका, लक्ष्य, जगह और समय तय करने की 'खुली छूट' दी गई थी। फिर अलग से ये मुलाकातें क्यों की गईं? बेशक सेनाओं को खुली छूट है, लेकिन वे अलग-अलग प्रधानमंत्री को तो ब्रीफ करेंगी कि यदि युद्ध की नौबत आई, तो उनकी क्या तैयारियां हैं? वायुसेना प्रमुख ने हवाई आक्रमण का खुलासा किया होगा! हाल ही में उप्र के शाहजहांपुर में 'गगा एक्सप्रेस वे' पर बनाई गई विशेष हवाई पट्टी पर राफेल, सुखोई, मिग-29, एएन-32, जगुआर, मिराज सरीखे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो का प्रदर्शन किया और रात्रि में लैंडिंग कर अपने युद्धाभ्यास को सार्थक किया। अर्थात हमारे लड़ाकू विमान किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं। नौसेना अध्यक्ष ने अरब सागर की हलचलों से प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया होगा! नौसेना ने विशालकाय आईएनएस-विक्रांत को समंदर में तैनात कर दिया है। वह लड़ाकू विमानों और परमाणु अस्त्रों से युक्त है। भारत ने परमाणु मिसाइल वाली पनडुब्बी को भी समंदर में 'सक्रिय' कर दिया है। नौसेना सुरक्षा और निगरानी को अधिक बढ़ाने के मद्देनजर भारत ने अमरीका की 'हॉक आई' खरीदने का 13.1 करोड़ रुपए का करार किया है। रूस से 'इग्ला-एस' मिसाइलें खरीदने का करीब 260 करोड़ रुपए का करार किया गया है। ऐसी कई तैयारियां होंगी, जो हमारी सेनाएं कर रही हैं, लेकिन न तो हमें पर्याप्त जानकारी है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हम उन्हें सार्वजनिक करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ सेना-प्रमुखों की ऐसी मुलाकातों और बैठकों में विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों, आपातकालीन जरूरतों, सेना-विशेष की चुनौतियों और उचित समय आदि पर खुल कर बातचीत होती है।

सेना-प्रमुख प्रधानमंत्री को अपनी सेना की तैयारियों और संभावित विकल्प पर तुरंत प्रहार करने की क्षमताओं को भी ब्रीफ करते हैं। इनके ये मायने नहीं हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध छिडऩे ही वाला है। भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने युद्ध संबंधी न तो कोई बयान दिया है और परमाणु हथियारों की धमकी तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के मंत्री और राजदूत परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के लगातार बयान देते रहे हैं। भारत में सेना-प्रमुख कोई भी बयान नहीं देते। यह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार देश को आश्वस्त किया है कि आतंकियों और उन्हें समर्थन देने वालों पर ठोस और निर्णायक कार्रवाई जरूर की जाएगी। यानी भारत के राजनीतिक नेतृत्व और सेनाओं के निशाने पर पाकिस्तान में बसे और सक्रिय आतंकी, उनके गुट और उनके पनाहगार हैं। देश के अनुभवी रक्षा विशेषज्ञों, जिन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल के पद पर रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाइयां और टकराव लड़े और झेले हैं, का मानना है कि इस बार आतंकियों के साथ-साथ पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा फौज को निशाना बनाया जा सकता है। वे भी नहीं जानते कि यदि भारत ने प्रहार किया, तो वह किस दर्जे का होगा, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई पर किसी किस्म का हमला किया जाता है, तो पाकिस्तान उसका पलटवार करेगा और वही युद्ध में तबदील हो सकता है। यह बाद की बात है कि पाकिस्तान युद्ध में कितने दिन तक टिक पाएगा, उसके पास गोला-बारूद तक पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस तरह युद्ध छिड़ सकता है। चीन पाकिस्तान को मदद दे सकता है। तुर्किये ने भी कुछ हथियार और रक्षा सामग्री पाकिस्तान को भेजी है, ऐसी खबरें आई हैं। पाकिस्तान एक विपन्न और विक्षुब्ध देश है, लिहाजा मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि वह बिन सोचे-समझे परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल कर सकता है। बेशक दोनों देशों ने परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल किया, तो विनाश व्यापक और भयावह हो सकता है। वह स्थिति टालनी चाहिए।

आओ कब्र खोदें

गतांक से आगे'

लेकिन आप अपने घर की खुदाई में बाहर क्या निकालोगे? मैंने पूछा। वह हंसते हुए बोले, 'क्या दिक्कत है? देश की भद पीटने वाला गोदी मीडिया 24 गुणा 7 तैयार बैठा है। अवतारी पुरुष की विष्ठा को भी हलवा साबित करने वाला गोदी मीडिया क्या किसी विधर्मी बादशाह के मुद्दे पर मेरा साथ नहीं देगा। गोदी मीडिया को अपने नेता के पक्ष में नारे ही तो लगाने हैं। फ्लॉप नोटबंदी, बुलेट ट्रेन या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को प्रजातांत्रिक राजा का मास्टर स्ट्रोक बताने वाला मीडिया क्या इस मुद्दे को हवा नहीं देगा। मैं पास के शहर के कब्रिस्तान से एक कब्र खुदवा कर एक कंकाल निकाल लाया हूं। नोटों में चिप ढूंढने वाला मीडिया ख़ुद साबित कर देगा कि यह कंकाल किसी मुसलमान शासक का है। अपनी तो पौ बारह है प्यारे। तुम्हारे देखते-देखते मैं किसी बड़े पद पर आसीन हो जाऊंगा। तुमने कई महीनों से मेरा सोशल मीडिया एकाउंट चैक नहीं किया है। मैं तो हर प्लेटफॉर्म पर सरकार, पार्टी और षड्यंत्रकारी संगठन के गुण गा रहा हूं। इतिहास में नए-नए नायकों को खोज रहा हूं। उनकी चिताओं से उनकी प्रतिमाएं घड़ रहा हूं। अपने लिए लडऩे वालों को देशभक्त बता रहा हूं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का साथ देने की बजाय जब अंग्रेजों का साथ देने वालों के वंशज सरकार में मंत्री बन सकते हैं तो क्या मैं किसी संस्थान का मुखिया नहीं बन सकता?' उनके इस तर्क से हतप्रभ होते हुए मैंने पूछा कि क्या सिस्टम इतना भोंदू है कि अयोग्य व्यक्ति को भी ऊंचे से ऊंचे पद पर बिठा दे? वह तंज़ भरी नजऱों से मेरी ओर देखते हुए बोले, 'प्यारे! प्रजातंत्र की यही तो ख़ूबी है कि समाज के सोये रहने पर कोई अव्वल दरजे का मूर्खानंद, बहरूपिया और स्वार्थी भी देश का सरताज बन सकता है। दुनिया के तमाम देशों पर नजऱ डालो, तुम्हें स्वयं ही इसका जवाब मिल जाएगा। जो लोग किसी दफ्तर में चपरासी बनने के लायक नहीं, वे तमाम संवैधानिक पदों पर आसीन होकर दुनिया पर राज कर रहे हैं। लोग ऐसे मूर्खों के बयानों पर तालियां पीटते हैं और वाह-वाह करते रहते हैं। जिन्हें न बोलने की तमीज़ है और न मौके और लोगों का लिहाज, वे सार्वजनिक तौर पर उलटे-सीधे बयान देते रहते हैं और उनके अंधभक्त तथा गोदी मीडिया उन्हें जन-जन तक पहुंचाता रहता है।

क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अवतारी का पंचर वाला बयान या लाला रामदेव का शरबत जिहाद जैसे वक्तव्य किस लिए घड़े जाते हैं। अगर वक्फ में संशोधन से पहले मुसलमान युवा पंचर लगाते थे तो क्या यह क़ानून पास होने के बाद क्या वे हवाई जहाज़ उड़ाएंगे? दक्षिण के चार राज्यों में मंदिरों के पास दस लाख एकड़ ज़मीन होने के बावजूद अवतारी पकौड़े तलने को रोजग़ार बता रहे थे। जब अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा था तो सत्ता में बैठे भारतीय नेता, अंधभक्त और गोदी मीडिया वक्फ-वक्फ खेल रहे थे। गलवान झड़प और चीन द्वारा भारतीय भूमि पर क़ाबिज़ होने के बावजूद प्रधान सेवक का इससे इन्कार, फिर चीन के विरुद्ध किसी कार्रवाई के नाम पर टिक-टॉक का बायकॉट और अब ट्रंप टैरिफ के बाद चीन से गलबहियां तुम्हें हमारे राष्ट्रीय चरित्र के बारे में कुछ नहीं बतातीं? दुनिया भर के देशों और उनके नागरिकों ने ट्रंप टैरिफ का विरोध किया, धरने-प्रदर्शन किए और अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार किया। पर पहले तुम्हारे देश की सरकार के साथ नागरिक भी सोये रहे और अब इस घटना को चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अगर तुमने इतिहास पढ़ा हो तो पता चले कि प्लासी की लड़ाई में क्यों मु_ी भर अंग्रेज़ों ने भारतीयों की कमर तोड़ दी थी या क्यों उन्होंने दो सौ साल तक भारत पर राज किया।' इतना कहते-कहते वह गंभीर हो गए। लेकिन जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर यह सब प्रपंच क्यों घड़ रहे हैं? मैंने पूछा। कुछ देर शांत रहने के बाद झुन्नू जी बोले, 'बाज़ार में व्यापार ही किया जा सकता है, शांति पाठ नहीं। जब समाज और देश का चरित्र ही लिजलिजा हो तो उसमें रीढ़ के साथ जीना अपने जीवन को नर्क बनाना है। बेहतर है कि सत्ता के गुण गाओ और मटन-पनीर के साथ रोटी खाओ। ऐसे माहौल में दाल-रोटी खाने और प्रभु के गुण गाने की कल्पना करना बेमानी है।' उनकी इस व्यावहारिकता से प्रभावित होते हुए मैंने उनके श्रीचरण छुए और बहती गंगा में हाथ धोने का संकल्प लिए विदा लेकर बाहर निकल आया।

-पीए सिद्धार्थ

साजिशों का दौर और

सियासी सिकुडऩ में यह सिहरन कैसी, तेरे पांव की मेहंदी सफर पे नकली निकली। हिमाचल कांग्रेस के ताज को तख्त से शिकायत इतनी बढ़ गई कि अब सोशल मीडिया की तख्तियों पर बुखार चढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की एक पोस्ट ने चीरफाड़ शुरू की है, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने अपनी ही सरकार के फैसले को कुरेदना शुरू किया है। मुकेश अग्निहोत्री फरमाते हैं,'साजिशों का दौर है, झूठ के पांव नहीं होते।' इस पोस्ट के पीछे कसक है-कटौती है या गहरे पानी से निकलता कोई ज्वारभाटा, यह कांग्रेस का विलाप है जो किंकर्त्तव्यविमूढ़ परिस्थितियों में 'आलाकमान' का दरबार सजा है। कांग्रेस में यह कौनसी साजिश है जिसे अग्निहोत्री सूंघ रहे हैं। विडंबना यह है कि पार्टी संगठन में अब अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया के समुद्र छाने जाते हैं। इससे पहले भी जब प्रदेश की सत्ता में तूफान आया था, तो इसकी पूर्व सूचना के लिए सोशल मीडिया की सुर्खियां आक्रोश की दिहाड़ी पर काम कर रही थीं। अब पुन: आक्रोश की दिहाडिय़ों को गिना जा सकता है। सरकार में मुकेश अग्निहोत्री का रुतबा अगर रंजिश के दांव-पेंच में साजिशें गिन रहा है, तो यह शुभ सूचना नहीं हो सकती। यह सत्ता के मुलायम सफे कैसे हो सकते कि कोपभवन में सरकार के ही मुख्यमंत्री को अंदेशा है कि षड्यंत्र लिखा जा चुका है या झूठ के तराजू में इंसाफ हो रहा है। ये इशारों की भाषा में सत्य की कथनी हो सकती है या राजनीतिक सियारों की हूक भी हो सकती है, मगर दोनों ही स्थितियों में कालिख के कालीन पर कांग्रेस चल रही है। संगठन चुनावों के छिलके इतने उतर चुके हैं कि पार्टी फिर पुराने दौर के दोराहों पर दिशा भ्रम के संघर्ष में कमजोर-लाचार दिखाई दे रही है।

इसी परिप्रेक्ष्य में ठियोग के विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस फैसले को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां सरकार शिमला को कुछ कार्यालयों के बोझ से निवृत्त करने जा रही है। पर्यटन विकास निगम मुख्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने को अंतिम मोहर लग चुकी है, तो ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने प्रश्नों का बखेड़ा करके इस फैसले को विरोध के मोर्चे पर खड़ा कर दिया है। व्यवस्था परिवर्तन की जिस टोह में मुख्यमंत्री निकले हैं, वहां शिमला के दबाव को मुक्त करने की गुंजाइश खोजी जा रही है। ऐसे में ताल से ताल मिलाने के बजाय राठौर ने विरोध की रार ठोंकी है। सियासत जब दुकान बनती है, तो हर मापतोल पर व्यापार होता है। आश्चर्य यह कि सरकार के हर फैसले पर अपनों की निगाह और अपने ही गवाह। गवाही यह कि उप मुख्यमंत्री को शिकायत है, तो एक विधायक को फैसला पसंद नहीं आया, तो मीडिया-मीडिया खेल शुरू हो गया। ऐसे में बिखराव के इस मंजर पर अनुशासित होने के लिए आदेश कौन पारित करेगा। इन दोनों नेताओं ने अपनी बात कहने के लिए सोशल व मेन स्ट्रीम मीडिया का ही प्रयोग क्यों किया। अपनों के साथ बात करने का तरीका अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दूरियां हैं या फैसलों से फासले पैदा हो रहे हैं। आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन यहां तो मकबरे चिन कर बताया जा रहा है कि कोई सुला दिया गया नमाज पढऩे से पहले। आश्चर्य यह कि अन्य राज्यों के भूत अब प्रदेश कांग्रेस के पलड़े पर आकर बैठे महसूस हो रहे हैं। अपनी ही पार्टी अपनी ही सत्ता के शिकायती टोकरों में मुंह छिपाती घूम रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को उपमुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि साजिश के ऊंट किसके रेगिस्तान में घूम रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के विरोध का चारा अगर कांग्रेसी नेता ही खाएंगे तो सरकार के लिए घर के हालात पर गौर फरमाने की जरूरत बढ़ जाती है।

दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने अजय टम्टा परिवहन राज्यमंत्री को उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही ज्यादतियों के खिलाफ ज्ञापन सौपा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री अजय टम्टा जी परिवहन राज्य मंत्री भारत सरकार से मिल कर उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही ज्यादतियों के खिलाफ उन्हें अपनी मांगो का ज्ञापन सौपा.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने मंत्री जी को बताया की उत्तराखंड सरकार का परिवहन विभाग उत्तराखंड से बाहर की टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर- बसों की हिल फिटनेस (ग्रीन कार्ड) 6 महीने की बजाये हर बार 15 दिन मेँ कर रहा हैं.

संजय सम्राट ने मंत्री जी को बताया की पेहले हर टैक्सी बस के फिटनेस के 600 रुपए 6 महीने के दिए जाते थे, लेकिन अब हर 15 दिन के बाद 600 रुपए फिटनेस के लिए दिए जाएंगे. वास्तव में सच्चाई यें हैं की उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोई भी टैक्सी बस बगैर दलाल के फिटनेस नहीं मिलती. और 600 रुपए फिटनेस के अलावा दलाल का खर्चा हर फिटनेस पर 3900 रुपए होता हैं. इसलिए एक धार्मिक चारधाम यात्रा भ्ष्टाचार की यात्रा दिल्ली,हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स के लिए बन गई हैं.

दूसरा कारण उत्तराखंड की कुछ ट्रांसपोर्टर्स यूनियन का दबाब उत्तराखंड सरकार पर हैं और उन्ही के दबाब में उत्तराखंड से बाहर की दुसरे राज्यों की टैक्सी बसों को बार बार चेक करने के बहाने उनके ड्राइवर्स का भारी भरकम जुर्माना किया जा रहा हैं बल्कि दहशत भरने के लिए उत्तराखंड से बाहर राज्यों की टैक्सी बसों को छोटी छोटी बातो पर जब्त किया जा रहा हैं, जिस से दुसरे राज्यों की गाड़ियाँ उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में पर्यटको को लेकर ना जाए और उत्तराखंड के लोकल ट्रांसपोर्टर्स को सारा काम मिल सके. ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव श्री जगदीश पाण्डेय ने मंत्री जी से शिकायत करी की उत्तराखंड सरकार का परिवहन विभाग पूरे भारत की टैक्सी, टूरिस्ट टेम्पो ट्रेवलर- बसों वालो से दोहरा रवैया अपना रहा हैं. पेहले उत्तराखंड मेँ चारधाम यात्रा के सारी टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर- बसों को हिल फिटनेस (ग्रीन कार्ड) 6 महीने के लिए मिलता था. लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्यों की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या अपने राज्य के ट्रांसपोर्टर्स को फायदा देने के लिए सिर्फ उत्तराखंड की टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर- बसों की हिल फिटनेस 6 महीने रखी हैं. और उत्तराखंड के बाहरी राज्यों की टूरिस्ट टेम्पो ट्रेवलर- बसों की फिटनेस हर बार 15 दिन मेँ कर रहा हैं, सबसे बड़ी बात यें हैं की अगर हमारी टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर- बस 15 के लिए चारधाम पर गई हैं और पहाड़ खिसकने से या रोड टूटने से ट्रैफिक जाम के कारण हमारी गाडी वापिस 15 दिन की बजाये 16 या 17 दिन मेँ आये तो बगैर फिटनेस के यहाँ का ट्रांसपोर्ट विभाग हमारी गाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाएगा और गाड़ियों को जब्त भी करेगा.

एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर्स सरदार दलजीत सिंह ने मंत्रीजी को बताया की उत्तराखंड की ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन उत्तराखंड से बाहर के राज्यों की टूरिस्ट गाड़ियों के चालको को मारती और धमकाती हैं बल्कि कल ऋषिकेश मेँ कुछ गाड़ियों को तोड़ा भी गया हैं और ड्राइवरों को बुरी तरह पीटा गया. पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के आयोजन सचिव सरदार हरविंदर सिंह ने मंत्री जी से कहा की हमारी टूरिस्ट गाड़ियाँ आल इंडिया परमिट का पूरा टैक्स भरकर उत्तराखंड जाती हैं लेकिन वहां की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और यूनियन जब हम रेलवे स्टेशन या एयर पोर्ट से टूरिस्ट को गाड़ियों मेँ बिठाते हैं तो यें रंगबाजी दिखाकर हमारे चालको को मारते हैं और टूरिस्ट को हमारी गाडी से उतारकर जबरजस्ती अपनी गाडी मेँ बिठाने की कोशिश करते हैं. बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए की हर टैक्सी बसों से हफ्ता वसूली करते हैं, पुलिस और प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ हैं. ऐसा मुझे काफी ड्राइवर्स ने बताया हैं की पुलिस को कॉल करने पर वो कुछ कार्यवाही नहीं करती. क्योंकि गाडी मेँ टूरिस्ट बैठे होते हैं तो मजबूरी मेँ इनको हफ्ता देना पड़ता हैं.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मंत्री जी से मांग की उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए जाए की उत्तराखंड की बाहरी टूरिस्ट गाड़ियों की भी हिल फिटनेस पेहले की तरह और उत्तराखंड की टूरिस्ट गाड़ियों की तरह एक बार मेँ ही 6 महीने की फिटनेस दें. जिससे भ्रष्टाचार को लगाम लगे और अफरा तफरी का माहौल वहां खत्म हो सके. साथ ही उत्तराखंड के बाहरी राज्यों की गाड़ियों और चालको को सुरक्षा प्रदान करी जाए.

ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री अजय टम्टा जी ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की एक मीटिंग उत्तराखंड के परिवहन सचिव से फिक्स कराई हैं और उनको फ़ोन करके निर्देश भी दिया की दिल्ली के ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओ का इनसे मिलकर समाधान किया जाये, परिवहन मंत्री जी ने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को अस्वासन दिया हैं की वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से बात करेंगे और ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओ का जल्दी समाधान करवाएंगे.

जल्दी ही ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तराखंड के परिवहन सचिव से मिलने देहरादून उत्तराखंड जायेगा।

पुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़शिा

भूबनेश्वर : पुरी अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी दे दी है। सोमवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इन दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।इस संबंध में केंद्र ने कहा कि भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान जगन्नाथ का निवास पुरी एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है, जो देश और दुनिया भर से लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुरी में हवाई अड्डा स्थापित करने के निर्णय से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय विकास और समग्र सम्पर्क को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।

यह हवाई अड्डा पुरी और भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों के बीच सीधा हवाई संपर्क बढ़ाने में मदद करेगा। यह निर्णय पुरी और ओडिशा के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है और इससे हवाई संपर्क मजबूत होगा। यह कदम हवाई यात्रा को सभी के लिए किफायती बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप उठाया गया है।

बैठे-बैठे हाथ-पैर हो जाते हैं सुन्न! जानें क्यों होती है झुनझुनी और कैसे पाएं इससे राहत

अक्सर शरीर में पोषक तत्वों की कमी और नसों में कमजोरी की वजह से बैठे-बैठे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल में जानेंगे क्या है झुनझुनी (Tingling Sensations) का कारण किस की विटामिन की कमी (Vitamin B12) से होती है यह समस्या और कैसे पाएं इससे राहत।

नई दिल्ली। क्या आप उन लोगों में से है, जो जिन्हें अचानक बैठे-बैठे हाथ-पैर में झुनझुनी होने लगती है। क्या आपको ज्यादा देर बैठे रहने से हाथ-पैर या अन्य हिस्स में झुनझुनी (Tingling Sensations) महसूस होती है? अगर हां, तो इसे हल्के में न लें। ऐसा होने कई बार आम हो सकता है, लेकिन हर बार यह आम नहीं है। शरीर में होने वाली झुनझुनी की कई वजह होती है, लेकिन इसकी एक मुख्य वजह शरीर में एक विटामिन की कमी होती है।

दरअसल, शरीर में एक खास तरह के विटामिन की कमी से न्यूरोन की एक्टिविटी प्रभावित होती है, जिसकी वजह से झुनझुनी होती है। आइए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं किस विटामिन की कमी से होती है झुनझुनी और कैसे करें इसकी कमी को दूर-

क्यों होती है झुनझुनी?

यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के सही विकास और इसे सेहतमंद रखने के लिए सभी पोषक तत्वों का होना बेहद जरूरी है। विटामिन-बी12 इन्हीं में से एक है, जो शरीर में कई जरूरी काम करता है। हालांकि, कई बार कुछ वजहों से शरीर में इसकी कमी होने लगती हैं और इसकी कमी ही झुनझुनी का कारण बनती है।

क्यों विटामिन-बी12 से होती है झुनझुनी?

मेडिकल की भाषा में समझें तो जब शरीर में विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency) होती है, तो इसकी वजह से कई तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने लगती हैं। पैरों में पेरेस्टेसिया और मांसपेशियों में ऐंठन इन्हीं समस्याओं में से एक है, जो मांसपेशियां और नसों में कमजोरी का कारण बनती है और इसकी वजह से नसों में झुनझुनी महसूस होती है। इसके अलावा विटामिन-बी12 की कमी चक्कर आना, थकान और डिप्रेशन कारण भी बन सकती है।

इन वजहों से भी होती है झुनझुनी?

पैरों में विटामिन-बी12 की कमी झुनझुनी का कारण बनती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ यही इसकी वजह है। हाथ-पैर पर चढ़ने वाली झुनझुनी दूसरे विटामिन की कमी से भी हो सकती है। साथ ही शरीर के किसी हिस्से में खून की सप्लाई में कमी, नर्व डैमेज, ऑटोइम्यून डिजीज भी झुनझुनी की वजह बनती है।

कैसे दूर करें विटामिन बी12 की कमी

अगर आपके शरीर में विटामिन-बी12 की कमी हो गई है, तो डाइट में तुरंत मीट, मछली, अंडा शामिल करें।

अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो दूध, पनीर और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स की मदद से भी विटामिन बी12 की कमी दूर हो सकती है।

इसके अलावा डाइट में फोटिफाइट फूड्स को शामिल करने से भी विटामिन बी 12 की पूर्ति हो सकती हैं।

साथ ही मोटा अनाज खाने से भी शरीर को जरूरत के मुताबित विटामिन बी 12 मिल जाता है।

अपनी रेगुलर कॉफी को दें एक हेल्दी ट्विस्ट! जी हां, इसमें हल्दी मिलाकर पीने से मिलते हैं दोगुने फायदे

हल्दी एक ऐसा मसाला है जो सदियों से अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड होता है। ऐसे में जब आप इसे अपनी कॉफी में मिलाते हैं तो यह एक सुपर ड्रिंक बन जाती है जो आपको एनर्जी के साथ-साथ कई हेल्थ बेनिफिट्स (Turmeric Coffee Benefits) भी पहुंचाती है। आइए जानें।

नईदिल्ली। कई लोगों के दिन की शुरुआत एक कप हॉट कॉफी के साथ होती है। यह न सिर्फ हमारी सुस्ती को दूर करती है, बल्कि दिनभर की एनर्जी और मानसिक ताजगी पाने का भी एक बढ़िया तरीका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी रोज की कॉफी को थोड़े हेल्दी ट्विस्ट के साथ और भी फायदेमंद बनाया जा सकता है? जी हां, आपकी रेगुलर कॉफी में हल्दी मिलाकर न सिर्फ उसका स्वाद और रंग बदल सकता है, बल्कि इससे आपकी सेहत को भी बहुत सारे फायदे (Benefits Of Adding Turmeric To Coffee) मिल सकते हैं। आइए, इस आर्टिकल में विस्तार से आपको बताते हैं इसके बारे में।

हल्दी वाली कॉफी पीने के फायदे

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का खजाना

हल्दी में 'कुरक्यूमिन' नामक तत्व होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट है। यह शरीर में सूजन को कम करता है और दर्द को राहत देता है। अगर आप जोड़ों के दर्द या शरीर में सूजन से परेशान हैं, तो हल्दी वाली कॉफी इस समस्या में मदद कर सकती है।

इम्युनिटी बूस्टर

हल्दी का एक और खास फायदा है कि यह आपकी इम्युनिटी को बढ़ाती है। यह शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत देता है। जब आप हल्दी मिलाकर कॉफी पीते हैं, तो आपका शरीर और भी मजबूत होता है और बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है।

डिटॉक्सिफिकेशन

हल्दी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, यानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। रोज हल्दी वाली कॉफी पीने से आपकी त्वचा और शरीर साफ और हेल्दी रहते हैं।

फोकस में सुधार

हल्दी में मौजूद तत्व मानसिक शांति और ताजगी बढ़ाते हैं। यह मस्तिष्क के कार्यों को उत्तेजित करता है, जिससे आपकी एकाग्रता में सुधार होता है और मानसिक थकावट दूर होती है।

हार्ट के लिए फायदेमंद

हल्दी के नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल स्तर कंट्रोल में रहता है। यह हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देती है और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम करती है।

हल्दी वाली कॉफी बनाने का तरीका

सामग्री:

1 कप कॉफी

1 चुटकी हल्दी पाउडर

1/2 चम्मच दारचीनी (ऑप्शनल)

1 चम्मच शहद (या स्वाद अनुसार)

1/2 कप दूध (वैल्फेड मिल्क या प्लांट-बेस्ड मिल्क)

1/2 चम्मच अदरक पाउडर (ऑप्शनल)

बनाने की विधि:

सबसे पहले अपनी कॉफी तैयार करें- अगर आप इंस्टेंट कॉफी पीते हैं, तो उसे गरम पानी में घोल लें, या फिर अपने पसंदीदा तरीके से फ्रेश कॉफी बना लें।

अब इसमें हल्दी और दारचीनी (अगर आप पसंद करते हैं) डालें। हल्दी को अच्छे से घोलने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच शहद या शक्कर भी डाल सकते हैं।

अदरक पाउडर भी डाल सकते हैं, जो इसे एक अलग और फ्रेश स्वाद देगा।

अब इसमें दूध डालें और अच्छे से मिलाकर हल्की आंच पर गरम करें।

तैयार हो गई आपकी हल्दी वाली हेल्दी कॉफी, जिसे आप गरम-गरम परोस सकते हैं।

ये कैसा ट्रोल, जिसका नहीं है कोई मोल ?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम हमले में (22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में) अपने पति, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खोने वाली हिमांशी नरवाल को हाल ही में ट्रोल्स ने निशाना बनाया। दरअसल, वह लगातार शांति की अपील कर रही थी और उन्होंने पत्रकारों के सामने यह बात कही थी कि-'हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक, हम न्याय चाहते हैं, जिन्होंने ग़लत किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए।' यह बहुत ही अफसोसजनक है कि हिमांशी को ट्रोलर्स ने बुरी तरह से निशाना बनाया। कितनी बड़ी बात है कि मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ नफरत न फैलाने की अपील करने वाली हिमांशी नरवाल को ट्रोलर्स द्वारा निशाना बनाया गया और उन पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, यहां तक कि उन्हें हिंसा की धमकियां भी दी गईं। हिमांशी नरवाल ही नहीं, एक बच्ची से दरिंदगी के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों की मर्यादाहीन भाषा पर एतराज जताने वाली शैला नेगी को भी अभद्र टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहां पाठकों को यह बताता चलूं कि नैनीताल में मचे बवाल(मुस्लिमों को गाली दे रहे प्रदर्शनकारियों से भिड़ने पर) के बीच एक स्थानीय महिला शैला नेगी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें शैला नेगी प्रदर्शनकारियों से सीधे भिड़ती हुई नजर आतीं हैं, वीडियो के वायरल होने के बाद शैला नेगी को रेप तक की धमकी दी गई।

बहरहाल,इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है कि सोशल मीडिया आज धमकियों का प्लेटफार्म बन चुका है। वास्तव में, सोशल मीडिया पर आज किसी को भी ट्रोल करना, किसी व्यक्ति विशेष पर ऊल-जलूल और अभद्र टिप्पणियां करना, धमकियां देना, जो भी मन में आए वह कंटेंट डाल देना जैसी बातें आम हो चली हैं। यह बहुत ही शर्मनाक व अफसोसनाक बात है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज के समय में हम पाश्चात्य संस्कृति में जीने लगे हैं और भारतीय संस्कृति और इसके नैतिक मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को लगातार भूलते चले जा रहे हैं।सच तो यह है कि सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ ही आज हमारे समाज से नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। आज सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से लोगों में सहानुभूति की कमी, साइबर बुलिंग(बिना किसी डर के दूसरों को निशाना बनाना) और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोग अब अपनी निजता का सम्मान नहीं करते हैं और दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं कि वे एक सार्वजनिक स्टेज(मंच) पर क्या कह रहे हैं और वास्तव में उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए तथा इसका समाज और देश पर क्या और किस कदर प्रभाव पड़ सकता है? वास्तव में होना तो यह चाहिए कि सोशल मीडिया पर हम दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति दिखाएं, और उनके विचारों का सम्मान करें। सोशल मीडिया पर ग़लत सूचनाओं, जानकारी को शेयर ना करें और सोशल मीडिया पर अपने समय को सीमित करते हुए हम व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दें। हम जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन में, समाज और देश में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन हमें इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और नैतिक रूप से करना चाहिए, ताकि हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट न आए और दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। आज सोशल मीडिया पर सच्चाई और ईमानदारी की कमी सी हो गई है। हमारी यह आदत सी हो गई है कि आज हम सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी निजी जानकारी साझा करते हैं, जो हमारी निजता का उल्लंघन कर सकती है। यह नैतिक मूल्यों के विघटन का एक उदाहरण है, क्योंकि निजता किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज सोशल मीडिया पर अक्सर हिंसा और अभद्र भाषा का प्रसार होता है, जो हमारे समाज व देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सोशल मीडिया

मंच पर हमें अपने विचारों को और मान्यताओं को दूसरों पर थोंपने का कोई अधिकार नहीं है, क्यों कि सामाजिक समानता समाज के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम अपने स्वार्थों को भुनाने के लिए सोशल मीडिया पर नैतिक मूल्यों को, हमारे आदर्शों को, हमारी सनातन संस्कृति को लगातार त्याग रहें हैं, जो ठीक नहीं है। आज ट्रोलर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसा बर्ताव करते हैं, जिसके सामने कोई नियम-कायदा, नैतिकता या मर्यादा नहीं टिकती। हिमांशी नरवाल और शैला नेगी इसी ट्रेंड का शिकार हुई। होना तो यह चाहिए था कि इन दोनों का(हिमांशी नरवाल और शैला नेगी का) हमारा समाज साथ देता, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। हमारे देश के संविधान ने सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारतीय संविधान, अनुच्छेद 19 के तहत, प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भाषण, लेखन, मुद्रण, दृश्य प्रतिनिधित्व या किसी अन्य माध्यम से अपने विचारों, राय और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता का हकदार है, लेकिन इस आजादी का एक निश्चित दायरा है, एक सीमा है। वास्तव में हमारी अभिव्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता और गरिमा पर चोट करने वाली बिलकुल भी नहीं होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट डाला जाता है, बिना किसी डर और भय के। दरअसल, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हुए कई लोग इस बात को भूल जाते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक निश्चित दायरा है,एक सीमा है, गरिमा है। वास्तव में ट्रोलर्स को अपनी बात रखने, अपनी अभिव्यक्ति देने की अपनी आजादी तो नजर आती है, लेकिन इस अभिव्यक्ति के दौरान उन्हें सामने वाले के अधिकार और उसकी गरिमा, नैतिकता आदि का ध्यान नहीं रहता। यह बात ठीक है कि किसी व्यक्ति विशेष की बातों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन इसे व्यक्त करने का तरीका शालीन, सभ्य व नैतिकता को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए। वास्तव में सोशल मीडिया पर कंटेंट जानकारी परक, अच्छा, प्रासंगिक, विशिष्ट, मर्यादित होना चाहिए। कहना ग़लत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का दायरा बहुत ही व्यापक है और जब हम कोई बात ऐसे मंच पर कहते हैं तो यह बहुत दूर तक फैलती है, जाती है, क्यों कि इसकी पहुंच समस्त विश्व में है। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय हर किसी को इसके प्रभाव और पहुंच को लेकर हमेशा सतर्क व पूर्ण जागरूक रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हिमांशी नरवाल और शैला नेगी को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने वाले लोग नहीं हैं लेकिन दुखद बात यह है कि ग़लत चीजों को सपोर्ट करने वाले लोग आज कहीं अधिक नजर आते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया के सही उपयोग, प्रयोग पर गाइडलाइंस बनाईं जाएं और सख़्ती की जाए।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी सामग्री पर निगरानी रखने और गलत सूचना को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ,आम आदमी को भी यह चाहिए कि वे सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझें।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई पर विशेष... सुखद : विश्व एथलेटिक्स में बढ़ रहा है भारत का 'दबदबा'

प्रदीप कुमार वर्मा

फ्लाइंग सिख के नाम से देश और दुनिया में मशहूर मिल्खा सिंह। भारतीय उड़न परी के नाम से चर्चित पीटी उषा। दौड़ में नए मुकाम हासिल करती धाविका हिमा दास एवं पारुल चौधरी। और अपने भाले से लक्ष्य को भेदते नीरज चोपड़ा। यह कुछ नाम है जो भारतीय एथलेटिक्स के सितारे हैं और बीते दिनों में इन्होंने विश्व के खेल मानचित्र पर भारतीय पताका को फहराया है। इन एथलीट के दम पर ही विश्व एथलेटिक्स में भारत का दबदबा निरंतर बढ़ रहा है। यही नहीं यह भी तय है कि आने वाले दिनों में भी भारत की खेल पताका निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। विश्व एथलेटिक्स में भारत के बढ़ते दबदबे का आलम यह है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 134 पदक जीते। इतना ही नहीं भारत पहली बार इसी साल 2025 में प्रतिष्ठित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भी करेगा। विश्व एथलेटिक्स दिवस के मौके पर यह एक सुखद संकेत है।

एथलेटिक्स दिवस के इतिहास पर गौर करें तो पता चलता है कि विश्व एथलेटिक्स दिवस का शुभारंभ 1996 में विश्व एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा किया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य लोगों को खेल के फायदों के बारे में जागरूक करना है। जो उन्हें फिजिकल फिटनेस, टीम वर्क, सामंजस्य और खेल के महत्वपूर्ण मूल्यों के साथ-साथ सोशल स्किल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस के माध्यम से दुनिया भर के खेल प्रेमी, खिलाड़ी तथा अन्य नागरिक खेल के महत्व को समझते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 के लिए थीम है – "खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना।" इस थीम का मतलब साफ है कि एथलेटिक्स के जरिए भी नागरिकों में आपसी एकता एवं भाईचारा को बढ़ावा मिले।

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स चलाने और प्रबंधित करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह आईएएएफ और भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। एएफआई में 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।एएफआई का गठन 1946 में हुआ था और यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है तथा

भारतीय एथलेटिक्स के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। एथलेटिक्स दिवस 2025 का मुख्य उद्देश्य छात्रों और बच्चों की खेल आयोजनों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ स्कूलों और कॉलेजों के लिए विभिन्न खेल आयोजनों की शुरुआत करता है, ताकि खेल आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़े। इस आयोजन से कई एथलीट उभर कर आते हैं, जो देश और दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एथलेटिक्स में विश्व स्तर पर भारत के प्रदर्शन और बढ़ते दबदबे की बात करें तो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 134 पदक जीते। जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर वैश्विक मंच पर पैरा-एथलेटिक्स में अपनी बढ़ती ताकत और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। भारत ने इस बार के पेरा गेम्स में कुल 167 खिलाड़ियों का दल भेजा था और सबसे ज्यादा पदक जीतकर भारत ने अपना दबदबा साबित किया है। एथलेटिक्स के भविष्य के लिए यह एक सुखद संकेत है।

भारत के एथलीट के संबंध में बात करें तो दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह से लेकर वर्तमान में भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने भारतीय ट्रैक एंड फील्ड अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक अलग छाप छोड़ी है। फ्लाइंग सिख के नाम से चर्चित मिल्खा सिंह ने साल 1958 में टोक्यो में एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। वहीं,नीरज चोपड़ा टोक्यो 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। इसके साथ ही उड़नपरी के नाम से चर्चित पीटी उषा का एशिया में दबदबा और 2003 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज के ऐतिहासिक कांस्य पदक ने भारत को एक अलग ऊचांई पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। एशियाई रिकॉर्ड धारक और दो बार के कॉन्टिनेंटल शॉट पुट चैंपियन तजिंदरपाल सिंह तूर ने भी भारतीय एथलेटिक्स में एक अलग पहचान हासिल की है।

ट्रैक एंड फील्ड की भारतीय क्वीन ने साल 1982 से 1996 तक चार एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और चार स्वर्ण सहित 11 पदक जीते। एशियाई चैंपियनशिप में, पीटी उषा ने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर बाधा दौड़ और रिले स्पर्धाओं में 14 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते।

जीएसटी तथा आयकर विभाग की टीमें चाईबासा में पटेल के ठिकानों पर की छापेमारी

सिंहभूम मे लौह अयस्क,गिट्टी, ,सरायकेला मे क्रेसर,चावल मील के मालिक है मुन्ना व मनोज पटेल

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची/ सरायकेला, मंगलवार अपराह्न चाईबासा के न्यू कॉलोनी नीमडीह स्थित मनोज पटेल और उसके भाई मुन्ना पटेल के आवास पर आयकर तथा जीएसटी टीम का आगमन हुआ . फिर आरंभ हुई छापेमारी. पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क धड़ल्ले से जारी लौह कारोबार समय से कारोबारी रहे अब सरायकेला से 9 किलोमीटर दुर मिड़की पहाड में बड़ा क्रेसर अधिष्ठाता मनोज व मुन्ना पटेल इन दिनों झारखंड के काफी चर्चित व्यापारी माने जाते हैं .

मनोज पटेल का चाईबासा के हाट गम्हारिया में पत्थर तोडने गिट्टी बनने का क्रेशर है तथा सरायकेला के मिड़की में बड़ा पहाड़ तोड़कर गिट्टी तैयार करने वाली क्रेशर है. वही इसी जिले में राइस मिल भी है . जहां तक मिडकी से गिट्टी तैयार कर विभिन्न जगह भेजने की बात है यह यहां स्थित दो क्रेसर दिन रात एक कर विगत कुछ वर्षों से काम किये है .बताया जाता है इस छापेमारी में बड़ा जीएसटी चोरी की जांच की जा रही है . इसके पूर्व में भी इनके आवास पर छापेमारी हो चुकी है. विगत एक सप्ताह से केंद्रीय जांच एजेंसी की टीमों मिड़की , घोलाडीह , बाना आदि इलाके में भ्रमण करते देखा गया है ।

सनद रहे कि दो-तीन दिन पूर्व झारखंड खैनी के व्यावसायिक पार्टनर नितिन प्रकाश ,पंकज चिरानिया, पिंटू अग्रवाल के आवास और

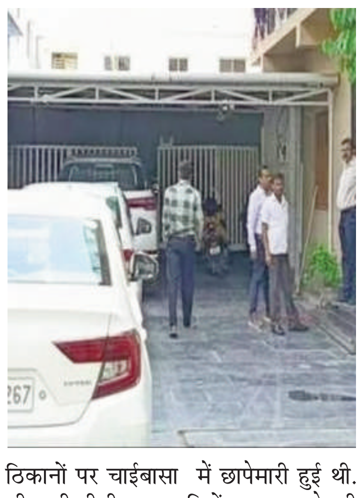

ठिकानों पर चाईबासा में छापेमारी हुई थी. जीएसटी की टीम द्वारा 2 दिनों तक यह छापेमारी चली .

आज करीब दो बजे में जीएसटी के रांची, दुर्गापुर ,जमशेदपुर, संभवतः बंगाल , ओडिशा के आला अधिकारियोंने धाबा बोला है . मनोज पटेल के आवास और ठिकानों पर छापेमारी हुई है.साथ ही क्रेसर इलाके में रेकी भी ।कार्यालय, ठिकाने में कागजातों को खंगाला जा रहा है. राइस मिल, गिट्टी , स्टोन क्रशर सहित विभिन्न व्यवसाय एवं निवेश व कारोबार से संबंधित कागजात और कंप्यूटर आदि डिजिटल साक्ष्यांकित जीएसटी के अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की जायेंगी ।

मनोज पटेल और मुन्ना पटेल दोनों भाई हैं और दोनों का पार्टनरशिप पर गिट्टी क्रेशर , राइस मिल और सभी व्यापार चलता है।

सुप्रीम कोर्ट का झारखंड हाईकोर्ट मे लंबित 67 अपीलों पर कडा रूख

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, झारखंड हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों में लंबे समय से फैसला लंबित रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के बाद 67 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा है कि ऐसे मामलों में एक महीने में रिपोर्ट दें, जिसमें फैसला सुनाना लंबित है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस घटनाक्रम को 'परेशान करने वाला' करार दिया. खंडपीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश बनायेगी. कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकता

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी हाईकोर्ट से 4 सप्ताह में उन मामलों पर रिपोर्ट मांगी है, जिनमें 31 जनवरी, 2025 को या उससे पहले फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन आज तक निर्णय नहीं सुनाया गया है. शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह निर्देश पारित किया, जिसमें कहा गया है कि जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2024

तक खंडपीठ द्वारा सुनी गयी 56 आपराधिक अपीलों में आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद फैसला नहीं सुनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एकल पीठ के न्यायाधीश के समक्ष आदेश सुरक्षित रखे जाने के बावजूद 11 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया गया है. शीर्ष अदालत आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 4 दोषियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इनकी पैरवी अधिवक्ता फौजिया शकील कर रहीं थीं. याचिका में दावा किया गया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर आदेश सुरक्षित रखा था, लेकिन फैसला नहीं सुनाया, जिसकी वजह से वे सजा में छूट का लाभ लेने में सक्षम ।

राजनीतिक दलों और जनता को देश के संविधान और सुरक्षा की सुरक्षा के लिए लड़ने की जरूरत: पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

ठूबनेश्वर : कांग्रेस द्वारा देवगढ़ उपजिला कार्यालय के सामने संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेम हेम्रम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भाग लिया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया ।पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि संविधान मजबूत होगा तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। राहुल गांधी ने संसद में जनगणना की मांग रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने जनगणना के लिए आंदोलन शुरू किया तो भाजपा ने डरकर जनगणना की घोषणा कर दी। आज के कार्यक्रम में पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नगेंद्र प्रधान, पूर्व सांसद यशवंत सिंह लागुरी, बासुदेवपुर विधायक अशोक दास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल लोचन तांडी, सुधांशु देव, दिलीप दुरिया, अभिषेक सेठ, दुर्गाशंकर पाढ़ी, केदार बरहिया और प्रियब्रत साहू समेत प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार में संविधान असुरक्षित होने पर जवाब देने का समय आ गया है।

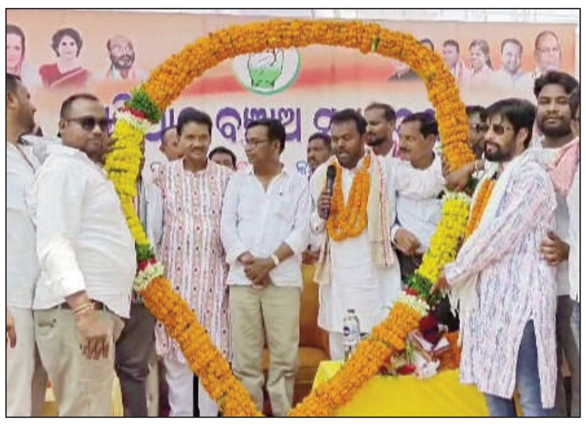

मिलेंगे ख़यालात...!

ये मत सोचा करो कि मिलेंगे ख़यालात,
उन्हें पास आने दो हम पूछेंगे सवालात।
बस एक बार दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना,
कोई नहीं चाहेगा तुम्हें सूली पर चढ़ाना।
यूँ हमने कभी-भी ना सीखा लड़खड़ाना,
तेरी शोखी ने किया है मेरा दिल दीवाना।
ये मत सोचा करो कि मिलेंगे ख़यालात,
उन्हें पास आने दो हम पूछेंगे सवालात।
इतना भी तो जालिम नहीं है ये जमाना,
उन घूरती नज़रों का कोई नहीं ठिकाना।
तुम हो इतनी हँसी कैसे हो नज़रें चुराना,
वे ढूँढा करते हैं तुमसे मिलने का बहाना।
ये मत सोचा करो कि मिलेंगे ख़यालात,
उन्हें पास आने दो हम पूछेंगे सवालात।
अब पता नहीं कब नज़रें होंगी इनायत,
मैं राह तकता हूँ तेरी करता हूँ जियारत।
इतना तड़पा के भी क्या मज़ा आता हैं,
दिल मेरा तेरी रुसवाई से बैठा जाता हैं।

संजय एम तराणेकर

विधायक समीर मोहांन्ती को पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बनाया झामुमो केन्द्रीय सचिव

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती को झामुमो का केंद्रीय सचिव बनाए जाने पर मंगलवार को चाकुलिया में विधायक कार्यालय सह पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मोहांती ने कहा मुझे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वास जताकर यह जिम्मेदारी सौंपी है , मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा ।

चाकुलिया नगर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद गुलाब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने फूल-माला पहना कर और मिठाई खिलाकर विधायक का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके नए पदभार के लिए शुभकामनाएं दीं। संगठन को मजबूती देने की उम्मीद जताई। विधायक समीर कुमार मोहंती ने कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन की मजबूती और जनहित के कार्यों के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। इधर विधायक मोहांन्ती को पार्टी सचिव चुने जाने पर उनके ससुराल सरायकेला से बंधाई का तांता लगा है ।

सायरन बजने पर घबराएं नहीं, सुरक्षा के लिए होगा मॉक ड्रिल: भजंत्री, डी एम- रांची

कार्तिक कुमार परिच्छा,स्टेट हेड- झारखंड

रांची, आपात काल की स्थिति में अपने नागरिक सुरक्षा को लेकर रांची में बुधवार शाम को मॉक ड्रिल किया जायेगा। इस संबंध में आज को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला आपदा पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री एवं डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची चंदन सिन्हा द्वारा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कियाा गया। वरीय पदाधिकारियों द्वारा मॉक ड्रिल के संबंध में मीडिया को आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला आपदा पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा बताया गया कि रांची के डोरंडा क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अपराह्न 04:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जायेगा।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला आपदा पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने डोरंडा क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मॉक ड्रिल नागरिक सुरक्षा के लिए अभ्यास मात्र है, इस दौरान सायरन बजने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने डोरण्डा क्षेत्र के लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान अपने-अपने घरों के लाइट्स बंद रखने की अपील की है। लोगों से अपने वाहन के लाइट और जेनरेटर आदि भी बंद रखने का आह्वान किया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि हम जिला वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं और भाग लेने वाले अधिकारियों को पूरा सहयोग दें। यह एक पूर्व-निर्धारित और नियंत्रित अभ्यास है जिसका उद्देश्य जन जागरूकता और अंतर-एजेंसी आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करना है।

मॉक ड्रिल के दौरान अपराह्न 04:00 बजे से अपराह्न 07:00 बजे तक डोरंडा क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होगी। ज्ञातव्य हो कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा।

"सोशल मीडिया पर देशविरोध का कारोबार: अभिव्यक्ति की आज़ादी या एजेंडा मार्केटिंग?"

सोशल मीडिया पर 'पेआउट' लेकर भारत को बदनाम करने वालों की अब खैर नहीं। IT एक्ट 2000 और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत सरकार ने सख़्त रुख अपनाया है। अब देशविरोधी कंटेंट पर न तो चुप्पी होगी, न छूट। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अफवाह फैलाने और एजेंडा चलाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसेगा। ये तय नहीं होगा कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके विचार भारत की अखंडता के साथ हैं या उसके खिलाफ़। अब पोस्ट से पहले सोचिए – देश पहले है, लोकप्रियता नहीं!

प्रियंका सौरभ

आज सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन चुका है, जिसकी धार किसी तलवार से कम नहीं। यह धार विचारों की है, भावनाओं की है और सबसे खतरनाक — अफ़वाहों की भी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसा अघोषित बाजार खड़ा हो गया है, जहाँ 'पेआउट' के बदले पोस्ट तैयार होती हैं, देश की छवि बिगाड़ी जाती है और एक सुनियोजित रणनीति के तहत राष्ट्रविरोधी एजेंडे को ₹न्यूज़र, ₹ऑपिनियनर और ₹न्यायर₹ का नाम देकर परोसा जाता है। लेकिन अब चेतावनी जारी हो चुकी है।

Standing Committee on Information Technology के हालिया कार्यालय ज्ञापन (Office Memo) ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की मंशा स्पष्ट कर दी है। अब सिर्फ़ देखा नहीं जाएगा — अब कार्रवाई होगी। आईटी एक्ट 2000 और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के तहत ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और 'इन्फ्लुएंसर्स' पर शिकंजा कसा जाएगा, जो देश के खिलाफ़ कंटेंट फैलाकर माहौल खराब करने में लगे हैं।

अभिव्यक्ति बनाम विध्वंस

देश में विचारों की आज़ादी संविधान से संरक्षित है। लेकिन क्या यह आज़ादी इतनी खुली हो कि कोई भी कुछ भी कह दे, और जब सवाल उठे तो 'डेमोक्रेसी', 'फ्री स्पीच' और 'डिसेंट' की आड़ ले ले? क्या राष्ट्रविरोधी कंटेंट को भी अभिव्यक्ति का हिस्सा मान लेना चाहिए?

जब कोई युवा ₹जॉब नहीं है₹ कहता है, वह जायज़ पीड़ा है। लेकिन जब वही सोशल मीडिया पर लिखता है — ₹भारत को जलना चाहिए₹, ₹हिंदुस्तान नर्क है₹, ₹देश तो फासीवादी बन चुका है₹, तो ये राय नहीं रह जाती — यह एक सुनियोजित अफवाह बन जाती है, जिसे राजनीतिक या विदेशी ताकतें और हवा देती हैं।

इसलिए अब ये तय नहीं होगा कि पोस्ट करने वाला किस पार्टी का समर्थक है, अब ये तय होगा कि पोस्ट का असर राष्ट्र पर क्या है।

'पेआउट पत्रकारिता' का बढ़ता जाल

आजकल कुछ 'फ्रीलांस' और 'इन्फ्लुएंसर्स' सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर ₹ज्ञान₹ दे रहे हैं। लेकिन इन ज्ञानियों के पीछे अक्सर छिपी होती है पेआउट की रणनीति। एक खास विचारधारा के तहत वीडियो बनाए जाते हैं — किसी पर आरोप मढ़ा जाता है, किसी की छवि बिगाड़ी जाती है और अंत में क्लाइमेक्स यह कि ₹भारत अब रहने लायक नहीं बचा।₹

ये सब उस एजेंडा मार्केटिंग का हिस्सा है जहाँ भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल की जाती है — खासकर मानवाधिकार, मुस्लिम विरोध, दलित उत्पीड़न जैसे संवेदनशील विषयों पर। इनकी टाइमिंग भी देखिए — जब UN में कोई भारत पर चर्चा होनी होती है, जब विदेशी रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक उन्हीं दिनों ये 'भारत-विरोधी अभियान' सोशल मीडिया पर तेज़ हो जाते हैं।

क्या देशद्रोह की पहचान पार्टी से होगी?

बहस का एक हास्यास्पद बिंदु यह भी है कि लोग यह तय करने की कोशिश करते हैं कि कोई विचार देशविरोधी है या नहीं, इस आधार पर कि पोस्ट करने वाला व्यक्ति भाजपा समर्थक है या कांग्रेस का आलोचक। लेकिन क्या भारत की अखंडता की पहचान दल से होनी चाहिए? क्या राष्ट्रहित को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा?

नहीं। अब समय है कि देश और दल के बीच की लकीर स्पष्ट की जाए।

राष्ट्र सबसे ऊपर है — न कि विचारधारा, जाति, धर्म या दल।

जो पोस्ट भारत की सीमाओं पर, उसके सैनिकों पर, उसकी न्याय व्यवस्था या लोकतांत्रिक संस्थानों पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें अस्थिर करने का काम करती है — वो राष्ट्रविरोध है। और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है — ऐसे कंटेंट को पेल दिया जाएगा, एकदम से तात्कालिक।

IT एक्ट और डिजिटल संहिता: अब छूट नहीं

आईटी एक्ट 2000 और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 अब सिर्फ़ किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे। जो लोग यह मानकर चल रहे थे कि ऑनलाइन की दुनिया 'नो रूल्स जोन' है, उन्हें अब ज़मीनी हकीकत से रूबरू होना होगा।

इन कानूनों के तहत:

राष्ट्रविरोधी सामग्री साझा करने पर प्लेटफॉर्म को नोटिस और कंटेंट हटाने का निर्देश

फर्जी न्यूज़ फैलाने पर आपराधिक मामला दर्ज

पेड प्रमोशन को खुलकर दर्शाना अनिवार्य

भारत विरोधी 'ट्रेंड्स' को बढ़ावा देने पर आर्थिक जुर्माना और बैन तक की कार्रवाई

इन कानूनी प्रावधानों को अब सरकार सख्ती से लागू करने जा रही है।

देश है कोई स्टोरी पिच नहीं!

भारत कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे 'इंटरनैशनल आउटलुक' में बेचने के लिए बदनाम किया जाए। यह देश करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मा और संघर्ष से बना है। कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचता है कि वो एक ट्वीट या एक रील के ज़रिए देश को नीचा दिखा सकता है, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है।

सोशल मीडिया पर चल रही यह ₹राष्ट्र-विरोधी आउटसोर्सिंग₹ अब नहीं चलेगी।

कलम अब ज़िम्मेदार हो

साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया और सोशल स्पेस — ये सब लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन जब यही प्लेटफ़ॉर्म विदेशी एजेंडों या राजनीतिक नफ़रत से ग्रस्त हो जाएं, तो उन्हें शुद्ध करना ही राष्ट्र की सुरक्षा का हिस्सा बन जाता है।

अब समय आ गया है कि कलम भी ज़िम्मेदारी के साथ चले।

हर पोस्ट से पहले, हर ट्वीट से पहले, हर वीडियो से पहले खुद से पूछिए — क्या ये मेरे देश के पक्ष में है या विपक्ष में?

अगर जवाब स्पष्ट नहीं है — तो पोस्ट मत कीजिए।

समापन में एक बात और —

ये देश बहस से नहीं डरता। लेकिन साजिश से चुप नहीं रहेगा।

अब वो दौर खत्म हो चुका है जब राष्ट्र को गाली देकर लोग 'लोकप्रियता' कमा लेते थे।

अब जवाब मिलेगा – कड़ा, कानूनी और तत्काल।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023